SHRI BHUPESH GUPTA: We, in the opposition, want to be treated with some amount of respect. It is for the Prime Minister now to have the next say. She should come and tell us whether she is going to tolerate such things. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down now.

SHRI BHUPESH GUPTA: We know of other minor charges or even suspicion, but here is a self-condemnatory document of the Minister Mr. Choudhury and yet he would like us to be silenced by him. I would like to hear the Prime Minister of the country and the Finance Minister on the very subject I have raised before you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kaiyanasundaram.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS— *contd.*

•SHRI RANCHI KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, on behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam Party to which I belong, I would like to express my views on the Motion of Thanks on the President's Address.

The attitude and the method adopted by some Members while the President was delivering his address in the Joint Session of the two Houses is regrettable. It is the right of every Member of Parliament to hear the address of the President in a clear manner. Those Members caused a lot of disturbance by shoutings- They did not bother about the impact of their behaviour on the mind of the public. Whatever it may be, the behaviour of those Members is regrettable.

In his address the President has referred to the establishment of a sovereign and independent Bangla Desh. The President has paid glowing tributes to the three wings of the armed forces who are responsible for the establishment of Bangla Desh. The President has rightly praised the bravery of our armed forces. In the same way the President has also paid tributes to the Indian people for their great sacrifices in their contribution to the establishment of Bangla Desh.

The people of Bangla Desh, unable to stand the repression in their own country by Pakistan took refuge in the Indian sub-continent. The Indian people welcomed them with burning enthusian and gave them food, clothing and shelter. This clearly shows the broad-mindedness of the Indian people.

The President in his address has emphasised the need for land reforms and ceilings on land. He has also referred to the problem of unemployment and the steps taken by the government to eradicate unemployment. The Government and the Planning Commission should take concrete steps to reduce unemployment.

The prices of commodities of daily necessity consumed by the people are rising particularly that of food. In this connection it is necessary to state the bare truth that the steps taken by Government to reduce prices have not been successful.

The President has referred to many proposals in his address. But it is disappointing to note that that in his address, the President has not referred to the powers of the Central Government and the distribution of Powers between the Central and the State Governments. The demand that the State Governments also should share the powers of the Centre is a long standing demand. An Hon. Member of this House—the Member who is leaving once for all after the expiry of his term —while referring to this demand in his speech stated that the demand of the D.M.K. Govem-ment for State Autonomy is a demand for 'Complete State Autonomy.' A new term 'complete State Autonomy' has been given to this demand.

But it has not stopped there. It has been further stated that the D.M.K.'s demand for complete autonomy was akin to self-determination under the cover of a threat, and it should be nipped in the bud. This is the charge made by the Member. The demand of the Dravida Munnetra Kazhagam for State Autonomy is a reasonable and justified demand but some insinuations have been made and motives have been imputed to it.

* Original speech in Tamil.

[Shri Kanchi Kaiyanasundaram]

In this connection, 1 would like to quote a passage from a great leader who had captivated the hearts of not only India but also the whole world, who was respected by the world leaders, who fought and defeated British Imperialism and secured independence for India and who was responsible for the framing of the Constitution of India. The following are his words:

"Wherein the said territories (the States) shall posssss and retain the status of autonomous units together with the residuary powers and functions of Government and administration."

These words are from none other tlian the Late Pandit Jawaharlal Nehru, which were adopted as a historic Resolution by the constituent Assenbly on the 22nd November, 1947.

I would like to assure this House that the Dravida Munntra Kazhagam will never even dream of endangering the unity of India. With these words I support the Motion of Thanks on the President's Address.

Thank you.

The House adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री उपसभापति : श्री राजनारायण ।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): हमको तो कहा गया था कि बाद में बोलना है ।

श्री उपसभापति : लंच के बाद में कहा गया था ।

श्री राजनारायण : यह कहा गया था कि शायद कोई दूसरा बोलने वाला है । तो शुरू करें हम ।

श्री उपसभापति : हाँ, कर दीजिये ।

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : ओम् गणेश आपसे ही हो जाय । मेरा नाम लेकर शुरू कर दो ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस समय जो अपने देश की स्थिति है उसको सदन के सम्मुख सफाई के साथ रखा जाय । मुझे अफसोस है कि इस समय प्रधान मंत्री महोदया यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं जो कि गरीबी मिटाने का नारा अक्सर देती रहती हैं और इस समय उन्हीं के नारे को कांग्रेस के लोग अक्सर दुहराया करते हैं । वास्तव में गरीबी मिटाने के नारे का अर्थ ही इस समय सत्ताधारी कांग्रेस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और यदि वे समझते हैं तो मैं समझता हूं कि जनता को भ्रम में रखने के लिये प्रयत्नशील हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि गरीबी है क्या, उस गरीबी का वर्णन थोड़ासा इस सदन के सम्मुख हो जाय ।

गरीबी की रेखा क्या है ? कितनी आमदनी तक, कितनी ऊपर या नीचे तक हम गरीबी मानें ? इसकी कोई परिभाषा होनी चाहिये । हम समझते हैं कि गरीबी की रेखा इस समय हमारे देश में अवश्य खींची जानी चाहिये और लोगों को मालूम होना चाहिये कि इतने रुपये तक की आमदनी के नीचे जो हैं वे गरीब हैं जिससे लोगों को मालूम हो कि सचमुच जो गरीब हैं उनकी कुछ तरक्की हुई या नहीं हुई, उनका कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ । गरीबी की रेखा कहाँ है ? प्रोफेसर दाँडेकर और प्रोफेसर रथ ने गाँव में प्रति व्यक्ति खर्च 15 रु० प्रति मास न्यूनतम आवश्यक माना है । इस प्रकार प्रति व्यक्ति 180 रु० साल न्यूनतम रेखा है । इसके नीचे ग्रामीण आबादी का 40 प्रतिशत आता है । यह 1960-61 की कीमत के अनुसार है । अब आप देखें 1960-61 में शहर की आबादी का 50 प्रतिशत इस रेखा के नीचे है । तो क्या इस आबादी को यह सरकार आगे उठाना चाहती है और कहाँ तक उठाना चाहती है । इस सरकार के पास क्या आँकड़ा है । सरकार इस सदन को अब इस देश की जनता को प्रधान मंत्री बता सकती हैं कि इस गरीबी का अर्थ क्या निकलता है । इसको कितनी

दूर तक ले जाएंगे, जिससे लोग समझें अपनी गरीबी यहाँ से यहाँ जा रही है ?

यह अनुमान बहुत कम कर के लगाया गया है। अपने देश में प्रति व्यक्ति अनुमान से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार की इकाई है। औसत परिवार पांच व्यक्तियों का है औसत परिवार के लिए प्रति मास कम से कम 150 रु० की आय जरूरी है। इससे कम को नितान्त गरीबी मानना ही चाहिए। इस तरह से वह परिवार जो 1,800 रु० साल से कम आमदनी वाला है, वह गरीब है। इस परिभाषा के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी के लगभग 50–60 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

गाँवों में जमीन की जोत का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 एकड़ से कम जोत वाले किसान परिवार कुछ किसान परिवारों के 74 प्रतिशत है। ऐसे किसान परिवार 5 करोड़ 31 लाख 30 हज़ार हैं। इस तरह लगभग साढ़े 26 करोड़ लोग 5 एकड़ से कम वाले परिवारों में हैं। ये भी गरीबी की परिभाषा में आते हैं। गाँवों की आबादी के 22 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो भूमिहीन हैं। गाँवों की आबादी लगभग 45 करोड़ है। इस तरह 9 करोड़ के लगभग तो भूमिहीन हैं, इनसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है ?

इसके अलावा आदिवासी, खेत–मजदूर, छोटे किसान, बूढ़े, विधवाएं, हरिजन, पन्द्रह बरस से कम उम्र के गरीब परिवारों के लड़के, लड़कियाँ, बेरोजगार, अपंग, भिखमंगे आबादी के गरीब वर्ग हैं। ये कुल जनसंख्या के लगभग 60 प्रतिशत हैं अर्थात् लगभग 33 करोड़। उनकी आमदनी डाक्टर लोहिया ने 3 आना रोज बतायी थी। प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 आना रोज कही थी, जो सरासर ग़लत थी। वह तो औसत आमदनी थी, गरीब वर्ग की आमदनी नहीं थी। तत्कालीन योजना मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने इसे खींच-तान कर साढ़े 7 आना रोज तक पहुंचाया था। नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक्स एण्ड रिसर्च ने लगभग साढ़े 4 आना माना था। तब से कीमतें दुगुनी हो गई हैं, इसलिए पैसे में देश के गरीब 60 प्रतिशत या 33 करोड़ की रोज की आमदनी 40–50 पैसे के लगभग है। इसे कम से कम 1 रु० रोज तक ले आने का मतलब है गरीबी हटाना।

तो मेरा कहना यह है श्रीमन्, कि आज 33 करोड़ आबादी अपने देश की गरीब है, जिसमें प्रति व्यक्ति आमदनी आठ आने से कम है, चालीस पैसा है, पैंतीस पैसा है, 30 पैसा है, 25 पैसा है। तो इस 33 करोड़ की आबादी को क्या आज कोई भी कांग्रेस का मंत्री या प्रधान मंत्री जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि एक रुपया तक ले जाएंगे, कितने साल में ले जाएंगे। उनकी गरीबी हटाने के मानी क्या हैं, गरीबी हटाने का अर्थ क्या है ? निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके जनता को गुमराह करना, बुद्धि-जन्य भ्रांति में विचरण करना, यह जनतंत्रीय परम्परा के अनुकूल चलना नहीं है।

श्रीमन्, यह भी बहुत कम है। देश काल, परिस्थिति के हिसाब से गरीबी की रेखा फिर ऊपर उठती और बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यदि हम देखें––अमरीका को ले लें, अमरीका में 4 आदमी के औसत परिवार के लिए 3,000 डालर प्रति वर्ष की आमदनी को गरीबी की रेखा माना गया है। गरीबी की रेखा 3,000 डालर है, इससे कम आमदनी वाले परिवार को गरीब माना गया है। रुपये के हिसाब से यह 22,000 रु० प्रति वर्ष के लगभग आता है। भारत में जिस परिवार की आमदनी 22,000 रु० है, वह उच्च मध्यम वर्ग का माना जाता है। नेता, मंत्री, अफसर, प्रोफेसर की औसत इस आमदनी से कम वाले हैं। अमरीका में निर्वाह भत्ते के द्वारा जो परिवार इस गरीबी की रेखा के नीचे है, उन्हें इस रेखा तक पहुंचाने का प्रयत्न होता है। जो 22 हजार रुपया प्रतिवर्ष से कम पाते हैं उनको अमेरीका के इस रेखा तक पहुंचाने के लिए यह सरकार क्या कोशिश करती है, उनको किस तरह की सबसिडी दी जाती है, किस तरह की सहायता दी जाती है और क्या यही गरीबी मिटाने का तरीका है। अमेरीका में एक आदमी की औसत आमदनी 3 हजार डालर मान ली गई

[श्री राजनारायण]

है, तो भारत सरकार ने आज गरीबी की रेखा क्या मानी है और मैं चाहता हूं कि आज सरकार इस बात को स्पष्ट करे। इस तरह से अमेरीका में इस रेखा तक पहुंचाने का प्रयत्न होता है और ऐसे परिवार वहाँ पर लगभग 20 प्रतिशत हैं।

सोवियत रूस में रोटी हर किसी के लिए मुफ्त कर दी गई है और इस तरह से भूख से लोगों को सहायता मिल गई है। गरीबी का दर्द आँकड़ों से नहीं जाना जा सकता है; क्योंकि यह तो अनुभव की चीज है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदया एक दिन इस गरीबी की अनुभूति करें और तब उन्हें पता लगेगा कि वे गरीबी मिटा सकते हैं। भारत में जिस परिवार की आमदनी 22,000 रु० है, वह उच्च मध्यम वर्ग का माना जाता है। नेता, मंत्री, अफसर, प्रोफेसर भी औसत इस आमदनी से कम वाले हैं। अमेरीका में निर्वाह भत्ते के द्वारा जो परिवार इस गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उन्हें इस रेखा तक पहुंचाने का प्रयत्न होता है। हमारे देश में इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इसलिए गरीबी की एक रेखा खींचनी चाहिए। जो इस रेखा के नीचे हो, 150 रु० माह से नीचे हों, उन्हें इस रेखा के ऊपर ले आने का मतलब गरीबी हटाना होता है, वरना गरीबी मिटाने का नारा जो दिया गया है वह अपने को धोखे में रखना है और देश की जनता को भी धोखे में रखना है।

यह भ्रम है कि आर्थिक विकास से अपने आप गरीबी हट जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से धनी और धनी हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं। राष्ट्रीय आय वृद्धि से ज्यादा महत्व-पूर्ण आय का वितरण है। गरीब वर्ग की बढ़ती हुई आय का जब ज्यादा भाग पहुंचे तो ही गरीबी दूर हो सकती है अन्यथा नहीं। सामान अवसर और विशेष अवसर जितने भी हैं, वे सब लागू होने चाहिएं।

उत्पादन में वितरण की विशेष आवश्यकता है। उत्पादन के साधनों का वितरण हो, विनिमय का वितरण हो और रोजगार में वृद्धि हो, प्रोफेसर दाण्डेकर के हिसाब से 800 करोड़—1,000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष नये रोजगार के लिये लगाये जायं तो कुछ हो सकता है, 25-50-75-100 करोड़ रु० से कुछ नहीं होने वाला है। श्रीमती इन्दिरा नेहरू गाँधी बजट को रोचक बना कर जनता को लुभाने की कोशिश करती रहती हैं।

शिक्षा क्या है? आज अपने देश में करीब 35 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। मैं जानना चाहता हूं 35 करोड़ अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए इस सरकार ने कोई योजना बनाई है। आज अपने देश में 25 करोड़ एकड़ जमीन असिंचित है, तो मैं यह जानना चाहता हूं 25 करोड़ एकड़ असिंचित जमीन है, उसको सिंचित करने के लिए इस सरकार के पास क्या योजना है।

आज देश में करीब 15 करोड़ एकड़ जमीन फालतू खेती योग्य है और उसको खेती के योग्य बनाने के लिए इस सरकार के पास क्या योजना है। हमने इस देश में शिक्षित दल बनाने की बात कही थी, हमने सिंचाई सेना बनाने का सुझाव दिया था और देश में खेतिहर पल्टन बनाने की बात कही थी, लेकिन भारत सरकार ने हमारे इन सब सुझावों की अपेक्षा कर दी और भारत सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। इस सरकार ने केवल लफ्फाजी और शब्दों का अनावश्यक प्रयोग करके जनता को भुलावे में रखा है।

श्रीमन्, आप देखते हैं कि राजनैतिक शक्ति जिनके पास है आज वे ही गरीब नहीं है। आज गरीब वे हैं जिनके पास राजनैतिक शक्ति नहीं है। इन दोनों चीजों का एक दूसरे से मेल-जोल है। यह तो कैसे हो। आज हमारे देश में जो विद्वत समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, गंगा बाबू जी से भी कहना चाहता हूं क्योंकि वे बड़े शान्त रहते हैं, उनके पास समय तो है, तो वे अपनी शान्ति बुद्धि से जरा समाज की सेवा करें। वे हमें बतलायें कि आखिर हम

कहाँ जायं और हम क्या करें। इस सरकार के पास आज कौनसी ठोस रचना है, जिससे इस देश की गरीबी दूर हो सके। हाँ, भ्रष्टचार बढ़ सकता है, कुन्बापरस्ती बढ़ सकती है, भाई भतीजावाद बढ़ सकता है, कुछ नये आफिसर निकल सकते हैं, इस तरह की सिद्धियाँ हो सकती हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास गरीबी मिटाने के लिए कोई योजना है। अगर उनके पास कोई योजना है और उसको जनता के सामने न रखना यह शुद्ध धोखा और सरासर शरारत है।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जरा हम लोग दुनिया के पैमाने पर भारत को आज देख लें कि हम कहाँ हैं क्योंकि हम बहुत फुदकते हैं और फुदकते हैं यहाँ के रेडियो में, यहाँ के टेलीविजन में और यहाँ की सरकार के प्रभाव में चलने वाले जो अखबार हैं उनमें। लोग कहते हैं प्रधान मंत्री की हवा चली। कहाँ चली हमने देखा नहीं, प्रधान मंत्री की हवा हमें दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, यह जरूर देखा कि किसी ने धन कमा कर रखा और उसके धन के ऊपर डाका पड़ गया, मगर हवा चली यह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। आज हमारी आय कितनी है, जो सरकारी आँकड़े हैं 1967-68 के उनके मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय 548 रुपए है, जब कि जापान की 8,415, ब्रिटेन की 10,883, पश्चिमी जर्मनी की 12,625, अमरीका की 26,835, कुवेत की 30 हजार और पाकिस्तान की भी 847 रुपया है।

श्री टी० एन० सिंह (उत्तर प्रदेश): 1967-68 की प्राइसेज पर यह इनकम 375-376 से ज्यादा नहीं है।

श्री राजनारायण: आपने ठीक कहा। दूसरे विश्वव्यापी युद्ध के बाद भारतवर्ष भी आजाद हुआ। जर्मनी जर्जर हो चुका था, जर्मनी कहाँ से कहाँ गया, ब्रिटेन ध्वस्त हो गया था, ब्रिटेन कहाँ से कहाँ गया। मैंने इसलिए यह दिखाने के लिए रखा है कि जब भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति सलाना आमदनी 548 रुपया है तो जापान की 8,415, जर्मनी की 12,625 और ब्रिटेन की 10,883 है।

भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति औसत खुराक 800 केलौरी है, जबकि दूसरे मुल्कों में 3,100, 3,200 और 3,300 है। आज सबसे ज्यादा किसी देश की ताकत को आँकना हो तो वहाँ के फौलाद को देखो। भारतवर्ष में फौलाद की प्रति व्यक्ति सालाना खपत है 11 किलोग्राम, ब्रिटेन में 422 किलोग्राम, सोवियत रूस में 428 किलोग्राम, पश्चिम जर्मनी में 579 किलोग्राम और संयुक्त राज्य अमरीका में 685 किलोग्राम है, चीन में भी 21 किलोग्राम प्रति व्यक्ति सालाना खपत है। चीन हमसे दो साल बाद आजाद हुआ, मगर चीन में हमसे दुगुनी खपत हो रही है। भारतवर्ष फौलाद में दुनिया में सबसे पीछे है। किस माने में हम शान लेते हैं। जब हम शान लेते हैं तो उसी तरह से लेते हैं जैसे मोर नाचता है तो अपनी टांग की ओर नहीं देखता और जब टांग की ओर देखता है तो नाच बन्द हो जाता है। इसलिए भारत सरकार रूपी जो मोर है, मैं चाहता हूं कि नाचने के पहले वह अपनी टाँग को देख ले, अगर टांग नहीं देखेगा तो टूट जायगी।

नूरुल हसन साहब, आप भी चहकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं। उनको पता नहीं कि उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। 10 हजार पर 23 ग्रेजुएट हैं भारत में, 140 हैं जापान में, 189 हैं रूस में और 350 हैं अमरीका में। डाक्टर 10 हजार पर 1 भारत में है और 500 पर 1 दूसरे मुल्कों में है। 10 हजार पीछे 20 टेली-फोन भारत में, 1,714 जापान में, 2,315 ब्रिटेन में और 5,431 अमरीका में यानी 2 पर 1। रेडियो, ट्रांजिस्टर भारत में 10 हजार पर हैं 177, जापान में 2,547, ब्रिटेन में 3,176 और अमरीका में 14,313 यानी 1 पर डेढ़। कर्जा जगजाहिर 1970-71 के बजट के अनुसार— इधर विदेशी कर्जा 8,200 करोड़ हो गया है— 7,762 करोड़ देशी ऋण है और 7,326 करोड़ विदेशी ऋण है। अगर यह कर्जा हम भारत के

[श्री राजनारायण]

आदमियों पर बाँट दें बराबर तो हर आदमी 274 रुपए का कर्जदार है।

भारत सरकार ने यह दयनीय स्थिति अपने देश की बना दी है कि हम आमदनी में सबसे पीछे, हम शिक्षा में सबसे पीछे, हम पढ़ाई में सबसे पीछे, हम फौलाद में सबसे पीछे, हम खुराक में सबसे पीछे। अब जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को भी जरा आप देख लीजिये। उत्पादन घट गया है, कपड़े का उत्पादन घट गया है, चीनी का औसत उत्पादन फी व्यक्ति घटता जा रहा है। सरकार को शर्म नहीं आती है। यह चिड़िया की तरह फुदक-फुदक कर उड़ती है और एकदम वितंडावाद है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि हरिजनों के उत्थान के लिये इस सरकार ने ठोस काम क्या किया है।

एक प्रकार से हम 1946 से आजाद हैं। हम हैरत में थे कि प्रधान मन्त्री महोदया कहा करती थीं कि स्टेबिल गवर्नमेंट चाहिये, स्थिर सरकार चाहिये, स्थायी सरकार चाहिये। हम चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नज़ीर दे। है कोई दुनिया में जनतन्त्रीय मुल्क जहाँ एक पार्टी की सरकार 27 साल तक लगातार रही हो। भारतवर्ष में एक पार्टी नहीं, एक परिवार की सरकार रही है और 27 साल लगातार रही है। केवल 18 महीने के लिये बीच में बेचारे लाल बहादुर शास्त्री जी आये। तो एक परिवार की सरकार 27 साल रही, फिर भी पेट का पानी नहीं मरा, फिर भी स्थिरता चाहिये, फिर भी स्थायित्व चाहिये। प्रधान मन्त्री महोदया कहती रही हैं चुनाव के दौरान कि जिसकी केन्द्रीय सरकार उसी की राज्य सरकारें। वे डिक्टेटर होना चाहती हैं।

भूपेश गुप्त जी आजकल बहुत प्रसन्न हैं। सोचते हैं कि इनको कुछ सीटें ज्यादा मिल गई हैं। मगर में अपने मित्र भूपेश गुप्त जी को चाहता हूँ कि वे जरा समझदारी से काम लें। वे हमारी बात को याद कर लें कि दो ढाई वर्ष में भूपेश गुप्त जी को रोना पड़ेगा और वे रोएंगे। मार्क्सवादी भाई हमारी बात को नहीं मानते थे और आज वे रो रहे हैं। उन्हीं को लेकर वर्तमान सरकार ने हम लोगों को पीटा था। उस समय मार्क्सवादी भाई नहीं बोलते थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भाई नहीं बोलते थे, आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जाको पिया माने वही सोहागिन, सोहागिन बनी हुई है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि भूपेश गुप्त जी की पार्टी का सुहाग लुटेगा और तब भूपेश गुप्त जी हमारी बात को मानेंगे। यही मैं इनको बता रहा हूं कि दो ढाई साल ज्यादा से ज्यादा लगेगा, इस बात को भूपेश गुप्त जी मान लें। मैं चाहता हूं कि आज हमारे सभी समझदार भाई इस पर विचार करें कि यह तानाशाही है या नहीं कि जिसकी सरकार दिल्ली में उसी का राज्य, उसी की जिला परिषद्, उसी की गांव पंचायत और उसी की एक शृंखला चलेगी। इस तरह एक डिक्टेटर बोलता है। जनतंत्रीय पद्धति में आस्था रखने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कह ही नहीं सकता। भूपेश गुप्त जी की बुद्धि पर हमें यकीन है। मैं उनको पंच मानने के लिये तैयार हूं। जब वे पंच की हैसियत से काम करेंगे तो गड़बड़ नहीं करेंगे।

मैं एक नज़ीर दे दूं। चुनाव हो रहा है और प्रधान मन्त्री सेना के जहाज से दौरा कर रही हैं। प्रतिनिधि कानून में लिखा हुआ है कि सेना के जहाज और सेना के आदमियों का इस्तेमाल नहीं होगा। 20 लाख से 25 लाख तक रुपया प्रतिदिन जनता के कोष से प्रधान मन्त्री ने खर्च किया है कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार पर। यही जनतंत्र है। इसी को जनतंत्र कहेंगे।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश): 20 लाख रुपये रोज नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण: रोज रोज। हर मीटिंग में दो लाख रु० का औसत है और एक एक दिन में आठ, दस, बारह, तेरह मीटिंगें ऐड्रेस की गई हैं। हैलीकाप्टर से वे जाती हैं, जिला

के अधिकारी और तमाम अफ़सर हर जगह मीटिंग आयोजित करते हैं। उसका पूरा खर्चा जोड़ा जाय तो करोड़ों करोड़ रुपया अब तक राज कोष से खर्च हुआ है, जनता का धन खर्च हुआ है और जनता के धन पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है।

शर्म नहीं आती है? यह जनतंत्रीय प्रणाली है? इसी को जनतंत्र कहते हैं? हमें याद है श्रीमन्, फरुखाबाद का चुनाव हो रहा था और डा० राम मनोहर लोहिया लड़ रहे थे डा० केसकर के मुकाबले में। लोगों ने पं० जवाहर-लाल जी को कहा कि आप चले जाइये। उस समय जवाहरलाल जी नहीं गये। उन्होंने कहा कि यह उप-निर्वाचन है, मैं उप-निर्वाचन में नहीं आऊंगा। मधु लिमये मुंगेर से लड़ रहे थे। जवाहरलाल जी को लोगों ने कहा कि आप चले जाइये, वे नहीं गये। मगर ललित नारायण मिश्र जो दरभंगा में चुनाव लड़ रहे थे तो उनके उस उप-चुनाव में प्रधान मंत्री साहिबा जाती हैं। उसमें सुरक्षा मंत्री जी जाते है, वित्त मंत्री साहब जाते हैं, कृषि मंत्री साहब जाते हैं और इसी चुनाव के बीच में 30 लाख की मिथिला पेंटिंग्स खरीदी जाती हैं पोलैंड की सरकार के जरिये। यह क्या विदेशी धन का दुरुपयोग नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि 5 करोड़ का कम्युनिस्ट देशों के लिए श्री ललित नारायण मिश्र ने व्यापार किया, मिथिला पेंटिंग्स का व्यापार किया, क्या यह चुनाव को प्रभावित करने की बात नहीं है? श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य जरा इन तथ्यों को भी देखें।

यह फोटोस्टेट कापी है एक चेक की। यह चेक है तारीख 4-1-72 का, जे० के० सेंथेटिक लिमिटेड कानपुर का 25,000 का, कोअरसिंह कालेज, दरभंगा के नाम। यह दूसरी फोटोस्टेट कापी है उसकी इसे देखा जाय। 3 तारीख को ललित नारायण मिश्र जी का नामिनेशन फाइनल होता है और 4 तारीख को जे० के० सेंथेटिक, कानपुर कोअरसिंह कालेज के लिए चेक काटता है 25,000 का।

श्री महावीर त्यागी: कालेज के नाम चेक काटने से क्या होता है?

श्री राजनारायण: यह चेक ललित नारायण जी मिश्र के भाई डा० जगन्नाथ मिश्र लेकर जाते हैं प्रिंसिपल के पास। पहले तो उसके चेयरमैन थे श्री बी० एन० सिंह, उसके पास गये। डा० बी० एन० सिंह ने कह दिया कि मिश्र जी, समय नष्ट मत कीजिए। मैं समाज-वादी हूं। मेरा वोट तो समाजवादी दल के राम सेवक यादव को पड़ेगा। आप समय नष्ट मत कीजिए। तब यह 25,000 का चेक उनके भाई प्रिंसिपल को जाकर दे आये और कहा कि एक लाख का चेक चुनाव के बाद देंगे। जब मालूम हुआ डा० बी० एन० सिंह को तो उन्होंने प्रिंसि-पल को बुलाया और कहा कि हमने दस-दस, बीस-बीस और पचास, सौ रुपया मांग-मांग कर तो यह कालेज बनाया और आज तक इस तरह से इसका खर्च चलाया और अब रिश्वत के पैसे से तुम कालेज चलाओगे। तुमको शर्म नहीं आती, तुम वोट बेचना चाहते हो। वह कालेज वहां अपना प्रभाव रखता है। उसका इंफ्लुएंस उस क्षेत्र पर है, तब यह कोअरसिंह कालेज के प्रिंसिपल लिखते हैं:

"Dear Dr. Misra,

I regret to have received a liberal donation of Rs. 25,000 on 11-1-72 from you for Kunwar Singh College vide Cheque No. HC. B/AE-781116, dated 4-1-72, in favour of the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur, just on the eve of the election.

I am returning the cheque with thanks.

Thanking you,

Yours sincerely, RAM BINOD. Kunwar Singh College, Laheriasarai. Darbhanga.

तारीफ कीजिए उस प्रिंसिपल की, उसने उस 25,000 के चेक को लौटा दिया, उस पर लात मार दी। उसको फेर दिया और यह

[श्री राजनारायण]

चिट्ठी है जिसका फोटोस्टेट है, सिगनेचर हैं ओरिजनल जगन्नाथ मिश्र के जो श्री ललित नारायण मिश्र जी के लघु भ्राता हैं और जो उनके इलेक्शन इंचार्ज हैं । वे राज भवन में रहते थे । इसमें लिखा है :

"Received one sealed envelope from the Principal, Kunwar Singh College, Laheria-sarai, containing a cheque for Rs. 25,000 only.

DR. JAGANNATH, MISHRA
Camp Raj Guest House,
Darbhanga. 19-1-72."

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa): Whal rubbish:

श्री राजनारायण : यह श्री ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई हैं, उस समय कौंसिल के मेम्बर थे विहार की । यह चेक उन्होंने रिसीव भी कर लिया जब प्रिंसिपल ने लौटाया और उसमें दस्तखत कर के दे दिया कि हाँ, जो आपने चेक लौटाया वह हमें मिल गया । यह एक है । ऐसे अनेकों चेक हैं । मैं आश्चर्यचकित हूं । मैं भूपेश गुप्त को न्यौता देता हूं, श्री नीरेन घोष और भूपेश गुप्त जी चले जायं और जा कर देखें कि दरभंगा में क्या सही तरीके से वोट से जीते हैं ललित नारायण मिश्र । दो लाख वोट से यह जीत गये । यह शोहरत थी ।

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश): आपका जमाना लद गया ।

श्री राजनारायण : मैं आपसे थोड़ा डरता हूं । आप सुन लीजिये । आप बहुत बड़े हैं ।

श्री कल्याण चन्द : मैं आपसे बड़ा नहीं हूं । बड़े छोटे की बात नहीं ।

श्री राजनारायण : सुनिये। बाबू सत्यनारायण सिंह 1967 ई० में जब लड़े थे तो 1 लाख 43 हजार वोट पाये थे और जीत गये थे । श्री विनोदा-नन्द झा जब 1971 ई० में लड़े तब केवल पार्लियामेंट के मेम्बर का चुनाव हुआ था और वह 1 लाख 30 हजार वोट पाये और जीत गये और रामसेवक यादव 1 लाख 77 हजार वोट पाये और फिर भी हार गये । 1 लाख 30 हजार पर श्री विनोदानन्द झा साहब जीते और 1 लाख 77 हजार रामसेवक यादव हारे । क्या कारण है ? कारण यह है कि जबरदस्ती बैलेट पेपर्स छीने गये, मुहर लगा दी गई जबरदस्ती । कौन नहीं मारा गया, जितने हमारे भूतपूर्व मंत्री थे सब पीटे गये, हमको घेरा गया, पीटा गया ? हमारे झा पीटे गये, राम इकबाल पीटे गये, तमाम पीटे गये । कलेक्टर को लिखित रपट है सबकी कि 40 हजार के करीब गुंडे आ रहे हैं उनको आने मत दो । एक दम सवेरे साढ़े पाँच छः बजे तीन-तीन सौ, ढाई-ढाई सौ या दो-दो आदमियों ने तमाम पोलिंग स्टेशंस को घेर लिया, वोटर्स को जाने नहीं दिया, करीब तीन सौ या साढ़े तीन सौ पोलिंग स्टेशंस दरभंगा में थे, जहां इन्होंने ऐसा किया, तमाम पोलिंग स्टेशंस को घेरा, वोटर को जाने नहीं दिया, वोट को पड़ने नहीं दिया यह स्थिति है ।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : फिर 1 लाख 77 हजार वोट कहाँ से आ गये ।

श्री उपसभापति : राजनारायण जी, आपने आधा घंटा ले लिया ।

श्री राजनारायण : मैं आ रहा हूं, श्रीमन् । मैं आपको कहना चाहता हूं कि दरभंगा में पाँच दिन पहले बैलेट पेपर बाँट दिया गया था । पाँच दिन पहले ।

श्री कल्याण चन्द : अरे !

श्री राजनारायण : पाँच दिन पहले । वह कहाँ था बैलेट पेपर । एक प्रिसाइडिंग आफिसर की एक बैलेट पेपर की गड्डी एक होटल में छूट गई थी । वह होटल में तीन घंटे के बाद लौटा कि हमने बैलेट पेपर की गड्डी छोड़ दी । बाद में होटल वाले ने वह उनको दे दी । तो हेलीकाप्टर का प्रयोग, सरकार का प्रयोग, सरकारी साधन का प्रयोग !

श्री कल्याण चन्द : गलत ।

श्री राजनारायण : गुंडों का प्रयोग ।

श्री कल्याण चन्द : गलत ।

श्री राजनारायण : और यह सेंट्रल रिजर्व पुलिस का प्रयोग । सेंट्रल रिजर्व पुलिस क्यों गई बिहार ? क्या बिहार की पुलिस काफी नहीं थी । बिहार की पुलिस थी । क्या सेंट्रल रिजर्व पुलिस इसलिये बढ़ाई जा रही है कि जब चुनाव हों तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस के बल पर चुनाव जीते जायं और इसको जनतंत्र कहा जाय और जिस पर कि हमारे विपिन पाल दास, जो एक मर्तबा हमारी पार्टी के एक जेनरल सेक्रेटरी रह गये हैं वहाँ पर जा कर जोर से गरजते हैं । शर्म नहीं आती इन लोगों को । कहाँ से कहाँ चले गये ।

श्रीमन्, क्या हुआ है बंगाल में ? बंगाल में हुआ क्या ? बंगाल में चुनाव के बाद ही आप देख रहे हैं कि कत्लेआम हो रहा है । हमारे पास एक खबर आई है कि दर्जन लोग चुनाव के बाद कत्ल कर दिये गये हैं 11 तारीख के बाद । यह अभी-अभी हमको खबर दी गई है ।

(*Time bell rings.*)

उलीवेरिया साउथ कांस्टीटुएंसी, हावड़ा में एक दम जो लेफ्ट फ्रंट के जो कैंडीडेट थे, उनकी ड्रैगिंग की गई । तमाम लोगों को परेशान कर के भगाया जाता है, परेशान किया जाता है, लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आठ बजे के अन्दर-अन्दर आप स्थान छोड़ दीजिये वर्ना आपकी जानमाल की हम हिफाजत नहीं कर सकेंगे । यह सारी की सारी चीजें हो रही हैं ।

वोट पड़ता है 801 और नम्बर मिलता है 810 । यह क्या है ? एक पोलिंग बूथ में 801 वोट पड़ने हैं और 810 नम्बर हैं । यह सब बिहार में देखा है । एक प्रिसाइडिंग आफिसर को हवलदार ने गोली मार दी । क्यों हवलदार ने गोली मारी ? 3 बजे के लगभग प्रिसाईडिंग आफिसर ने बैलट पेपर को निकाला और निकाल कर मोहर मारी थी' हवलदार को ऐसा पता चला कि ये अब चोर बैलट पेपर लिए जा रहे हैं, उसने गोली मारी । वह प्रिसाईडिंग आफिसर मर गया, क्योंकि प्रिसाईडिंग आफिसर कांग्रेस के पक्ष में मोहर डाल रहा था । तो यह जीत कोई जनतन्त्रीय जीत कह सकता है ? यह तानाशाही की जीत है, बेईमानी की जीत है, यह करोड़पतियों के धन की जीत है, यह तमाम करप्ट प्रैक्टिसेज की जीत है, क्या इसमें सभ्य मान्यताएं हो रही हैं, जनतन्त्रीय प्रथाएं हो रहीं हैं, इंसानियत हो रही है, मानवता हो रही है या सभ्य परम्पराएं हो रही हैं । अगर इसी तरह से हुआ तो मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है ।

श्रीमन्, मैं आपको बता दूं, अगर ये असेम्बली के चुनाव न हुए होते तो दरभंगा में पूर्वी बंगाल जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो सकती है; क्योंकि 1 बजे के करीब-करीब सारी काउन्टिग हो गई थी, वहाँ ललित नारायण के नाम के नारे ही नहीं लगे हैं, वहाँ पर दस-पाँच लड़के उनके पक्षपाती थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध कुछ बातें कहीं, कुछ हमको भी गालियाँ दीं । लेकिन फिर उसके बाद क्या जनता निकली है, क्या उनका नारा लगा है—जहाँ गई है याह्या-शाही वहीं जाएगी इंदिराशाही । यह दरभंगा की जनता का नारा है, शहर की जनता का । श्रीमन्, लोगों ने कहा, याह्या खां ने तो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी, इंदिरा-जी ने तमाम मतदाताओं को मत पत्र ही प्रदान नहीं किया, यह याह्या खां से ज्यादा बेईमान और खतरनाक है ।

श्रीमन्, मैं थोड़ा और 5 मिनट का समय लेकर खत्म करूंगा ।

श्री उपसभापति : 5 मिनट में खत्म कर देंगे ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं चूंकि राष्ट्रपति महोदय ने बंगला देश की बड़ी चर्चा की है और प्रधान मन्त्री महोदया

[श्री राजनारायण]

ने कहा है कि हमने 3 वचन दिए, उनको पूरा किया—मैं बंगला देश को आजाद करवाऊंगी, शरणार्थियों को वापस भेजूंगी, मुजीब को रिहा करवाऊंगी । मैं चाहता हूं श्रीमन्, आप साक्षी बनो, यह सदन साक्षी बने, दीवाल साक्षी बने, खम्भा साक्षी बने, कब कहा प्रधान मन्त्री ने बंगला देश को आजाद कराऊंगी—कभी कहा उन्होंने ? ग्रोमिको के साथ संधि में भी कहीं बंगला देश का शब्द नहीं आया, जर्मनी में, लंदन में, अमरीका में कहीं भी बंगला देश शब्द का प्रयोग नहीं किया । अगर बंगला देश आजाद कराने की बात कहीं थी तो तुमने 2 जून को हमको गिरफ्तार क्यों किया था, तुमने 12 अगस्त को हमको इस सदन में घसीटा क्यों ? झूठ बोलते हो, ग़लत बयानी करते हो । हाँ, 30 लाख लोग जो कत्ल हुए हैं बंगला देश में उनके खून से भारत सरकार का हाथ रंगा हुआ है । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं इसलिए कि आज ढाका में जाकर देखो । ढाका में वहाँ की पब्लिक भारत सरकार को गाली देती है कि भारत की सरकार ने हमको मार खिला दी । भारत सरकार उसको छिपाना चाहती है, इसलिए बंगला देश में जाने के लिए हम लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता । हमारे संपादक दीपक 3 दिन से दौड़ रहे हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिलता वहाँ जाने का । प्रधान मन्त्री ने कब कहा था मुजीब को रिहा करवाएंगे ?

श्री ओम् मेहता : पार्लियामेन्ट में कहा ।

श्री राजनारायण : अमरीका से जब प्रधान मन्त्री लौटने लगी हैं, उनसे पूछा गया कि मुजीब जिन्दा हैं या नहीं, तो प्रधान मन्त्री ने कहा है कि मैं नहीं कह सकती कि मुजीब जिन्दा हैं या नहीं मैं सोचती हूं कि शायद मुजीब इस दुनिया में नहीं है । (*Interruptions*) यह प्रधान मन्त्री का कहना था । अब वे कहती हैं, मुजीब को रिहा करवाऊंगी कहा था । वाह, छोटे मुंह बड़ी बात । हाँ, हमने कहा था । हमने बंगला देश को आजाद कराया । बंगला देश की जनता ने, बंगला देश के जवानों ने भारत के जवानों ने आजाद कराया ।

भारत के जवानों को जरूर बधाई देना चाहता हूं । हम छम्ब में गये, हम जोरिया गये, और शकरगढ़ गये थे । हमने अपने जवानों को अस्पतालों में भी देखा और मैं चाहता हूं कि बंगला देश की जाँच के लिए एक जाँच आयोग बिठलाया जाय और वह इस बात की जाँच करे कि बंगला देश में भारत सरकार ने क्या-क्या बंगलिंग की है और हजारों जवानों को लुंगिया पहिना कर कत्ल करवा दिया है ।

(*Interruptions*)

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : क्या आप निक्सन की तरफ से बोल रहे हैं ।

श्री राजनारायण : तुम ने लुंगी पहिना कर हजारों जवानों को कत्ल करवा दिया है । शर्म नहीं आती है । लुंगी पहिना कर हजारों जवानों को कत्ल करवाने वाली रानी, समझदारी के साथ कुछ करना, वरना देश की जनता निकाल कर सड़क पर फेंक देगी और जवाब तलब करेगी कि तुम्हें क्या हक़ था कि तुमने इतने हजार जवानों को लुंगी पहिना कर कत्ल करवा दिया ।

(*Interruptions*)

श्री सीताराम केसरी : (*Interruptions*) क्या ये पार्लियामेन्टरी बोली बोल रहे हैं, आप इन्हें रोकिये . . .

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप जरा तीन मिनट ठहरिये और उसके बाद आप ही बोलेंगे ।

श्री राजनारायण : पाकिस्तानी पल्टन के मुकाबले में और साधनों से बाहर जाकर भी हमारे जवानों ने अपनी प्रतिभा, अपना गौरव, अपनी कुशलता और अपनी कौशलता का परिचय दिया है । इन पल्टनी जवानों की जितनी

तारीफ की जाय उतनी थोड़ी है । हमने यह भी देखा कि हमारे इंजीनियरिंग विभाग वालों ने जहाँ पर पुरानी सड़क खराब हो गई थी उसकी जगह पर रातों रात नई सड़क तैयार कर दी । हमारे जवानों ने पाकिस्तानी टैंकों का ग्रेव-यार्ड बना दिया और पाकिस्तानी पल्टन को धाराशाही कर दिया ।

जहां तक भारत की जनता का सवाल है वह धन्यवाद के पात्र है और जहाँ तक पल्टन का सवाल है वह भी धन्यवाद के पात्र हैं । जहाँ तक भारत सरकार की राजनीति का सवाल है, उसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है । उसकी राजनीति ने देश को अपमानित किया है ।

श्री उपसभापति : आपके पाँच मिनट हो गये हैं ।

श्री राजनारायण : मैं एक दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । आप इन लोगों को रोकिये जो मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं और इस तरह से आपको मुझे पाँच मिनट और देना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि 11 दिसम्बर को यू० एन० ओ० में जब बंगला देश का सवाल उठा तो 104 मुल्कों ने हमारे विरुद्ध वोट दिया और केवल 11 मुल्क हमारे पक्ष में आये । इस तरह से यह भारत सरकार की टोटल राजनीतिक फेलियर हैं और यह बात 11 दिसम्बर की बात ने सिद्ध कर दिया है ।

इस सरकार ने 6½ करोड़ के नये टैक्स लगाये, 5½ करोड़ रुपये का अनावश्यक खर्च किया । इस सरकार ने नमक के दाम बढ़ा दिये, कपड़े के दाम बढ़ा दिये और चीनी के दाम 3½ रुपया किलो कर दिया । आज सारे देश में मिट्टी का तेल नहीं मिलता है और उसको गायब कर दिया, फिर भी यह जनता से वोट माँगती है । पब्लिक उसको क्यों वोट करे ।

श्री सीताराम केसरी : जनता ने तो सरकार को वोट दिया है ।

श्री राजनारायण : पब्लिक ने वोट नहीं दिया, बल्कि सरकार ने वोट की चोरी की, इस सरकार ने वोटों की चोरी की और मत पत्रों की डकैती की और इस डकेती से इन्दिरा की जीत हुई ।

हमारे समाजवाद की ये बातें है । समता, स्वतंत्रता, जनतंत्र, समाजीकरण, गैर-सम्प्रदाय, प्रवित्र साधन और क्रान्तिकारिता । समाजवाद-जनतंत्र-समता–स्वतंत्रता-सरकारी पूंजीवाद-भ्रष्टाचार-हिंसा-रूस तानाशाही इन्दिरा का समाज ।

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के भाषण पर बधाई देते हुए, 7-8 महीनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएँ घटी हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । 6 दिसम्बर को जब हमारी सरकार ने बंगला देश को मान्यता दी तो हमारे दोस्त श्री राजनारायण जी ने कहा कि उनके इस सदन से मार्शल द्वारा निकाले जाने के कारण देश में जनमत बना और इसी लिए बंगला देश को मान्यता मिली । इस सिलसिले में इतिहास का एक पन्ना मैं आपके सामने उलटना चाहूंगा । 1942 में जब गाँधी जी के नेतृत्व में क्रान्ति आई और उनके नेतृत्व में आजादी आई तो इनकी तरह चन्द नौजवानों ने कहा कि गाँधी जी क्रान्ति नहीं लाए हैं, क्रान्ति हम लोग लाए हैं, इस पर इनके गुरु और हमारे नेता स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक कहानी सुनाई अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी में, उन्होंने कहा कि जिस तरह से वे चिल्लाते हैं, उसी तरह से गुजरात में जब बैलगाड़ी सामान लादकर चलती है, तो उसके नीचे कुत्ता चलता है । तो गाड़ीवान से एक सिपाही ने कहा कि कुत्ते को ऊपर क्यों नहीं बैठाते तो गाड़ीवान ने कहा कि कैसे बैठाएं, यह कुत्ता कम्बख्त समझता है कि सारी गाड़ी का बोझ इसी के सिर पर है । यही हाल राजनारायण जी का है, कहते हैं कि क्रान्ति ये लाए, इनकी वजह से बंगला देश को मान्यता मिली । आप जानते हैं कि सारे देश में ये लोग हारे हैं, 1971 में जनता ने इनका कैसा स्वागत किया, 1972 में जनता ने इनका कैसा स्वागत किया ।

[श्री सीताराम केसरी]

यह सदन में पूंजीपतियों की ताकत पर चुन कर आते हैं और फिर इसी आधार पर उनकी बोली बोलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने सुना इनकी सारी बातों को। जनता की आवाज इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में थी, वे कह रही थीं कि समय पर मान्यता देंगे, जब मौका आया, परिस्थिति उपयुक्त थी, पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया तो हमने उसको मान्यता दी, उसको मुक्त कराया, आजादी दिलवाई। मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसी चीज का समर्थन करने के बजाय ये तुले रहते हैं गाली बकने के लिए। भगवान ने न जाने इनके मुंह में गाली के सिवा, अपशब्द के सिवा अच्छी चीज क्यों नहीं दी। जब एक बात कहते हैं तो समझते हैं कि सारी विजडम इनके साथ है। सारे पैसे वालों की विजडम, सारे केपिटलिस्टों की विजडम इनके साथ है। एक ओर समाजवाद की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि समाजवादी रहे। समाजवाद का चोंगा रखते हैं, मगर एक काम इनका वैसा नहीं होता है। चलकर देखिए, जनता में जाएंगे तो ऊट-पटांग बातें करेंगे, नतीजा यह होता है कि लोग थूकने की नौबत इन पर कर देते हैं। इस तरह की बातें कह-कह कर यह देश का ध्यान छोटी बातों की ओर ले जाना चाहते हैं। (*Interruption*) ये अब हमारी बातों को सुनने के लिए नहीं ठहरेंगे, जानते हैं कि सारी पोल खुल जायगी।

आपका ध्यान इस ओर दिलाने के अलावा मैं एक बात और कह देना जाहता हूं। देश में इतना बड़ा काम इन्दिरा जी ने किया, इस देश को 2500 सालों के बाद पहली बार गौरव दिया है और पहली बार इस देश ने एक मुल्क को आजाद कराया है, मुक्त किया है। आपने आज तक यह सुना नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि सिकन्दर आया, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए और यह देश पद्दलित और पदाक्रान्त रहा। इसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहने चाहिएं, एक बार सच्चाई को स्वीकार करते, लेकिन बोलते कैसे, सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो पूंजीपतियों की बोली कैसे बोलेंगे, निक्सन की बोली कैसे बोलेंगे, चाऊ की बोली कैसे बोलेंगे। इन्होंने कहा कि लूंगी पहन कर कत्ले-आम हुआ। मैं तो कहता हूं कि इस महान कार्य के लिए 10 हजार तो क्या 10 लाख आदमियों की भी कुर्बानी देनी पड़ती तो देनी चाहिए थी। जब इन्होंने बजाय तारीफ के ये शब्द कहे तो मुझे इनकी देश भक्ति में भी अविश्वास हो गया, देश के प्रति इनकी आस्था में भी अविश्वास हो गया।

एक चीज की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी हाल में शंघाई में, चीन में निक्सन और चाऊ की कम्युनिके में जो बातें निकलीं हमारे दोस्त जो सी पी आई एम के थे, कल वही सब कुछ दोहरा रहे थे कि काश्मीर में जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं है। उस कम्युनिके के शब्दों में और उनके शब्दों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही शब्द है। चाउ और निक्सन की कम्युनिके की तरह सी पी आई एम के दोस्त नीरेन घोष का वक्तव्य सीजफायर और काश्मीर की जनता के बारे में है कि उनको आजादी नहीं दी गई है। इस तरह का चार्ज हमारे देश की सरकार पर लगाना मैं समझता हूं कि देश भक्ति के प्रतिकूल है। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

DR. VIDYA PRAKASH DUTT (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, the President in has Address to the loint Session ot' the two Houses underlined the international situation. He pointed out the important developments that have taken place in the last two years an! particularly in the last few months. Ths President in his Address said that one of the most significant development that took. ' place was the meeting of Mr. Nixon with Mr. Chou En-lai and other Chinese leaders and the new international situation that has come about as a result of this meeting. I believe, Sir, that this has been a momentous affairs and that we in India must understand both the nature of this understanding and the implications of it. I hope, therefore, you will permit me to spend a few minutes on analysing the Nixon-Chou meeting as well as the contacts between China

and the United States and their meaning for us.

It was not noticed then at that time, but I believe that the United States policy started changing since Mr. Nixon was elected President, and since Mr. Nixon proclaimed his Guam doctrine in December, 1969. Until then 1 submit that the United States policy was predicated on the presumption that the United States should be ready to fight two and a half wars. It was based on the assumption of a war in Europe and a war in Asia simultaneously, and half a war consisted of being ready for any contingency anywhere in the world. As Mr. Nixon triumphed at the hustings in the United Sttes, the US President and the international situation changed substantially. The US strategy/scaled down to what I would call one and a half wars, that is to say, Mr. Nixon no longer believed that Washington would have to face wars both in Europe and in Asia at the same time. Washington nolongercounted as a serious or distinct possibility that China and the Soviet Union would fight together against the United States any more and, therefore, the United States need be ready only for one war at one time. In fact, this war was no longer to be with China.

The Guam doctrine, which I have talked about, went further than this. It struck down the earlier belief so vociferously propagated by Washington among its Asian allies and friends until recently that China would provoke a conflict in Asia. The US administration proceeded on the belief that China was not likely to provoke any conflict in Asia, that China was not likely to start any conflagration in Asia. The United States saw a new identify of interests with Peking, a new identify of views with Peking, a new area of understanding. The Guan doctrine, therefore, not only restricted the possibility to one and a half wars, but it also embarked upon what I would call a new Asianisation which was to be different from the previous Asianisation of Eisenhower's time, that is of making Asians fight Asians.This was a different kind of Asianisation. And I should like to make a submission here about the nature of this new policy of the United States, the new policy of China and this relevance to India. The old Asianisation, if you will recall, was sought to be worked through a set of military alliances with conservative anti-Chinese Governments in Asia. As we know, the United States through a number of military alliances brought together into one forum a number of its military allias. But the pievious j balance that the United States had tried to build up, that had failed. The Humpty Dumpty fell from the wall, and it could not be put together again. And Mr. Nixon saw this failure more tlian anybody else. And therefore, Sir, I submit that Mr. Nixon was in sarch of a new balance, a balance whose chief pillar of support would be reconciliation with China. It was obvious that a new assessment was under way in Washington, that a new strategy was in the offing and that a new policy was being unfolded in Asia. Dr. Kissinger was the co-author of this policy. And if I may remind the House, Dr. Kissinger is essentially a military security theorist. All his training has been in classical German tradition and this tradition has been the tradition of balance of power. And Dr. Kssinger believes only in the balance of power theory and nothing else. And that is why I have said that all his training was in classical German tradition and in the balance of power theory. And therefore, he is now engaged in creating a new balance of power, a new balance of force, in Asia. And his strategy is to create a new equation in Asia of the United States, China and Pakistan. All the old attempts had failed. A new attempt was now being made. And in this new equation that Mr. Nixon has set his heart upon, Pakistan had an important place but not India. Washington was so busy building up this new equation, this Washington-Peking-Islamabad equation, that it was upset over its strategy being upset by India. The developments in Bangla Desh and India's firm handling of the situation suddenly put a spoke tn the wheels of this new plan of creating a new United States-China-Pakistan equation in Asia. It was for this reason that the United States and China both were so annoyed at the developments in Bangla Desh and al India's suddenly emerging as a purposeful, strong and powerful country in South East Asia.

And if I may come to China now, China too had been steadily shifting its policies. The Chinese have also wanted to break the old power structure in the world. And Mao has always said, if I may remind this House,"Know your enemy" and concentrate against the chief enemy with all your resources. In the interests of fighting the chief enemy, you can subordinate your minor or secondary quarrels with others. Moscow is the chief enemy as far as Peking is concerned, the physiognomy has changed beyond recognition and the centre of hostility has shifted from Washington to Mocsow. Peking

[Dr. Vidya Prakash Dutt]

came to the conclusion that it was possible to achieve its objectives through a dialogue with the United States, and that the time was ripe for such a dialogue. And Mao spoke of the great reorganisation and the great new alignments taking place in the world. He obviously meant the new reorganisation, the new alignment of the United States, Peking and Islamabad against Moscow and India. Peking therefore responded eagerly to the overtures of Washinton. And I submit that both sides made concessions. The United States obviously made a concession when it recognised that ;China was one, that Taiwan was a bilateral issue between the mainland Chinese Government and the Government of Formosa. Therefore, Washington would gradually withdraw its forces from Taiwan. But the Chinese also made a concession. As 3 P.M. Mr. Rogers said in his statement in the United States on March 7 that China had agreed to shelve the issue of Taiwan for the time being. Therefore, obviously there has been a concession from both the sides. So, we can understand why Peking was annoyed with India for having come in the way of the new strategy for the evolution of a new Washington-Peking-Islamabad equation. I suggest, Sir, that the United States for 20 years had followed a policy of containment of China and Asia. So the core and the kernel of the U. S. policies in Asia was the containment of China. That policy has been abandoned; it has been given up. Similarly, for 20 years or more china had been regarding the United States as it chief enemy, the chief threat in Asia. That policy has also gone. That policy has also been given up. Therefore, the two sides find considerable common ground among themselves, and this common ground is there for all to see.

The President in his Address spoke about true relaxation coming. He hopes that true relaxation will come as a result of the Nixon-Chou meet This is his hope. But it is only a hops. I have a feeling that the President was expressing a mute apprehension in this sentence that there was a fear that this may not be true relaxation, that possibly this relationship was a negative relationship, that possibly this relationship was going to be used against others. If this relationship was not going to be used against anybody else, then nobody would have any quarrel with it. But all the evidence so far shows that this relationship for the present at least is a negative relationship, that it would be used against others.

At the same time, Sir, I would submit that the world is too complicated for a simplistic view of things and we need not rush to extreme conclusions. The United States and China are not in one camp, and all their interests do not converge. The United States relationship with the Soviet Union is also of fundamental importance. US relations with many other countries are also important. So also are the Chinese relations with other countries. And, therefore, it may be difficult for the two just to gang up against others. But I suggest that each of them will use this new relationship, the new opening towards the other as a fine lever of pressure in its dealings with other powers, big or small. This, to my mind, is the meaning of the Nixon-Chou mealing.

We are not against China. I am personally not at all against China. I regard Chinese civilisation as a great civilisation and China historically a great country. In fact, we have indicated many times, and I recall the various statements that the Prime Minister has made offering contacts with China. Therefore, it is for China to decide whether or not she would like to normalise relations, whether or not she would like to establish healthier rconditions. The ball is now in the court of China. It is for Peking to decide what kind of relationship it should have with us. So far as India is concerned, we are willing, no matter what our relations with other countries, to have normal healthy relations with China as well as with other countries of the world. In such a situation I suggest that India is naturally and logically cut out for an independent role in world affairs.

Some people have advised India to establish what they call a balanced relationship with all the big powers. We must, Sir, categorically reject the notion of so-called balanced relationship. What does that relationship mean? It would mean we do not follow independent policies. It would mean that we do not have a stand on any issue. It would mean that our policies should be determined by the desire to please, and by the fear not to offend, other big powers and other countries of the world It would mean a position of subservience, of servility and of subordination. I would there-

fore say it is for the big powers to strive to establish a balanced relationship with India by adopting just and fair policies and not for India to strive to establish a balanced relationship with them.

Some people abroad have found a sudden virtue in our non-alignment and they are now lecturing to us on the need for remaining non-aligned. For them our non-alignment, I am sure, would be co-terminous with neutralism, passivity, inertia and inactivity. If we are all that, then they would think that we are non-aligned. To my mind, the two essential qualifications of non-alignment are (1) refusal to join any military block and (2) the capacity to take independent decisions on all issues before the world. On both these counts, India is fully non-aligned. Non-alignment, I submit, has not only been a wave of the present but remains a wave of the future. There are many countries in South-east Asia and elsewhere who wish to day that they had been non-aligned earlier. Countries from Malaysia to Philippines now wish that they had been non-aligned earlier and are now striving to be non-aligned. Therefore, I suggest that it should be India's function to strengthen the role of non-alignment and to play a part in expanding the areas of peace. There can be no doubt now, and I think even the most doubting Thomases must have been convinced now, that the Indo-Soviet Treaty frustrated the plans of certain powers—that the plans were there, I think everybody would agree—to intervene in the crisis in this subcontinent and strengthened India's capacity to take independent decisions. I suggest to the Government that we should use this strength for reinforcing our non-alignment and our independence.

Today Bangla Desh is a reality and the re-emergence of India is also a reality. Those who fly in the face of facts, those who are unreconciled to the changed reality of this sub-continent, those who have made it their business to give aid and comfort to militarism in Pakistan and continue to give Pakistan wrong advice and insincere counsel, those who are fanning the flames of tension and conflict between India and Pakistan, should realise that the game which failed in East Bengal will sooner or later fail in West Pakistan also. It is my conviction, Sir, from a close reading of the events in West Pakistan that, of course, in a somewhat different way, similar forces as those in Bangla Desh will gather strength in Pakistan, too. Increasingly the people of Pakistan are going to demand democracy, freedom and social justice. The process of awakening has begun. The experience of history is that religion can bring people together but it cannot hold them together, and religion cannot be exploited as the basis of State. This is a lesson which our communalists here in India have to learn and which the communalists in Pakistan are just beginning to learn. I know that there are positive and negative forces and factors in Pakistan, that there is a sharp struggle going on between the two, between those who want the advance of freedom and democracy and good relations with India and social justice at home, and those who want to continue to depend on bigotry and intolerance and on religious hatreds. But I am sure of the outcome of the struggle and I say, we should proffer our hand of friendship to the people of Pakistan.

One chapter has ended and another has begun. The chapter of instigated and provoked hatred, unnatural divisions, intolerance ar.d bigotry, is coming to an end very soon. What the people of Bangla Desh and India were fighting for were the cherished values of freedom, equality, individual dignity. It was a struggle for a more just society. We have no quarrel with the people of Pakistan. We are, in fact, I would say, partners in the common struggle against dictatorship tyranny, suppression and exploitation. I would suggest, let us take the initiative, let there be an open border between India and Pakistan, let theic be a people-to-people diplomacy between India and Pakistan for a change, let the windows be open, let the channels of communication be open, let the people come to know each other. After all, we cannot resolve all our problems with Pakistan in one shot, in one stroke. The structure of friendship will have to be built brick by brick. And, therefore, among tlie first thing to be done is to promote trade and to promote individual contacts. I say let us take the initiative, let India show more magnanimity. We have no quarrel with the people of Pakistan. Let there be an open border between us, let there be open communications between India and Pakistan, let the people of this country and that country come to know each other more, let that process which was disrupted in 1947 resume again. 1 say in the end that the time is coming when the peoples of the three countries of this sub-continent will come together and that will be the day when the voice of India, Bangla Desh and West

[Dr. Vidya Prakash Dutt]

Pakistan wiH ba jointly heard in the councils of the world.

2/Lt. K. P. SINGH DEO (Orissa): Mr. Deputy Chairman, I take this opprtunity to pay my salutations and my respect to the gillant and brave men of the Armed Forces who have given us victory in this Indo-Pakistan war. And in this context I remember the words of Churchill during the battle of Britian when he had said, "Never has so much been owed by so many to so few." And it is in this context that the President's Address is a sad disappointment. Whereas before the elections we read in the newspapers that the Prime Minister had been writing personal letters to the widows of jawans and that the Government had come out with liberal schemes for pension and other concsssions, the President's Address does not make a mention of any of these concessions and these concessions are conspicuous by their absence from the Address. The victory which our Armed Forces have won in the Eastern Sector would have been more complete in the Western Sector if we had not had a hasty cease-fire two days before our Armed Forces were going to strike and if that action which was approved by the South Block here had not been nipped in the bud on the 17th evening, it would have given us a complete control of the Chamb area where today the Pakistanis are sitting tight, and their capacity for mischief, aided and abetted by both the Americans and the Chinese, would have been minimised, and, maybe, we might have got General Tikka Khan and his troops in Sailkot to surrender as General Naizi, and that would have solved the Indo-Pakistan problem for quite sometime. But we failed and we missed the bus miserably. Maybe, it has got us a political victory. But militarily and strategically, in my opinion, we have slipped badly. In his Address the President has made references to the paramilitary forces. And it is just a passing reference. Out Territorial Army, in particular, has done very well in the 1962, 1965 and even in the 1971 operations. It has done its role not only as a second line of defence, but it has fought with tlie regular army in the front line and it has faced the same bullets of the enemy forces as the regular army Ii is faced. But the sad thing today is that those people who are in the Territorial Army are civilians who arc asked to done military uniforms and go to the front line and fight side by side with our regular forces. They are uprooted from their civil avocations. There is no way of rehabilitating them and the Presidential Address has not promised them any benefit such as pensionary benefit. A T.A. Jawan is expected to serve for 15 years before retirement and an officer embodied is expected to serve till he reaches the age of fifty. After embodying him for 15 solid years and after extracting work out of an officer till he reaches the age of fifty years, what is the terminal gratuity they are given? A Jawan is given hardly Rs. 1,500 which comes to his one month pay per year of embodied service. And an officer at the age of fifty gets only Rs. 12,000 as terminal gratuity. As the Supreme Commen-der of the Armed Forces the President, and the Prime Minister in her capacity as such, have taken great credit for the massive military victory which our Armed Forces have won for us. I hope they will look into these matters also and see that justice is done to the members of the Territorial Army peisonncl.

Just at this time on the eve of President Bhuto's visit to Soviet Union, there is a sinister move on the part of the Soviet Union to force us into a collective security arrangement or another Tashkent type of agreement. Last time,after the 1965 operation, government here lost the territories which our Armed Forces had won for us over the conference table at Tashkent. They had won those territories with their blood and guts and lives. I sincerely hope—I can do nothing but hoping—that government will not repeat the same mistake this time and betray our Armed Forces by giving concessions to President Bhuto when he comes here. I also hope that they will not yield to any Pressurisation from the super powers or Soviet Union who has stood by us during the Indo-Pakistan conflict and return any of the territories which our Armed Forces have won for us. If it is done, that can do incalculable harm to our security and to our defence of the country.

We have lot of lessons to learn after the war. Especially this war has led to realignment of forces and brought out perfidious action of some of our allies during the Indo-Pakistan conflict and also for-reaching consequences are taking place in the Indian Ocean where various powers are trying to establish their bases. The Soviet Union has got its Navy and its expanding submarine arm; the Americans have their Enterprise and the Seventh Fleet setting up

communication basis; there is deployment of long-range under-watcr missle system and orbital bombarding system; there is decision by China to test its IRBMs and ICBMs; Japanese and Commonwealth Naval exercises are there; and various powers are interested in doing researches on the ocean beds there.

And, Sir, our own Navy, in this context, should be developed and our own technology as well as oceanography and nuclear technology should be viewed in the light of the motivation the technological and strategic motivation of the various powers. The Prime Minister has been saying that we will not go nuclear. 1 would like to urge, through you. Sir, upon the Government to take the people and Parliament into confidence and spell out the reasons why we should not go nuclear in spite of these developments, whether it is to our military or strategic benefit or not to go unclear or whether it is due to economic factors. Then only, Sir, I think, we will be able to contribute in a more worthwhile way.

Sir, the President's Address is again disappointing in that it does not mention anything about removing the inequalities, the regional imbalances, etc. and in this respect, 1 would like to say that my home state, Orissa, which is a very economically backward and underdeveloped region, needs constant attention of the Government, because the State Government does not have resources, adequate resources, of its own to develop it and to harness the great potentialities that are available. Orissa is also a flood-and drought-and cyclone-affected area. As you would have seen, Orissa, for the last fifteen or sixteen years, has had alternatively droughts and Hoods and during the last five years there were two unprecedented cyclones which broke the backbone and shattered the economy of ihe poor State of Orissa and in this respect, tlie State Government has been demanding from the Centre for some permanent solution to the problems of droughts and floods. I believe, Sir, the Dutch Export from the UN had also been sent to Orissa to study the cyclone situa-tij.i there and to suggest ways and means to minimise the effect of cyclone. So, I should be grateful if the Government could come out with concrete proposals and enlighten this House as to what they propose to do.

As far as *garibi hatao* and the removal of unemployment are concerned, well, it has served the Government well and it has served the Government as a platform on which the Government had received a massive mandate from the people not only in the mid-term elections to Parliament, but also in the recent Assembly elections. The steps which are being proposed to be taken or what the Government contemplates to do to achieve these two things are conspicuous by their absence. On the whole, Sir. this Address is disappointing and in my opinion, it is not even worth the paper on which it is written. There is one heartening feature in this Address and that is that the Government is trying to bring forward a legislation on air pollution. Sir, air pollution has created world-wide interest and even in the UN, pollution is a subject which is arousing the interest of all and air pollution cannot be taken up is isolation, but in its totality, along with environmental pollution, and the use of natural resources must be planned properly ar.d I hope, Sir, that the Government will give a deep thought to it and see that a comprehensive environmental pollution prevention programme is undertaken and concrete steps are taken in this direction.

Sir, before I conclude, I would like to mention that the year 1972 is the year for the Olympics and for a great and populous country like ours, the performance of our sportsmen in the Olympics has been very dismal. Although the gold medal won in an Olympic game does not go with the spirit of the Olympics, it does give an idea as to the quality of the sportsmen of our country.

Government have been in charge of promoting sports in this country for the last 25 years, ;u.d this is direct index ol the faflure i I its sports policy. J hope this time during iItc selections Government will see that there are fair selections.

There are 21 events in the Olympics, one of which is rowing in which our oarsmen have been very successful. For the last four seasons, we have been champions of South East Asia. I hope Government will see that there is a rowing representation in the Olympics this time.

Thank you very much.

श्री गंगाशरण सिंह (नाम-निर्देशित): जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे राष्ट्रपति जी ने पिछले वर्ष जो हमारे सामने भाषण किया था उसके बाद से और इस भाषण के दरम्यान देश और विदेश में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। राजनीतिक दृष्टि से हमारे देश के लिए, हमारे लिए उनमें चार घटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है—बंगला देश की मुक्ति का संग्राम और बंगला देश की मुक्ति, हमारे देश में, प्रदेशों में आम चुनाव, रूस के साथ भारत की मैत्री और उसके संबंध में जो बयान निकला वह और अमरीका के राष्ट्रपति की चीन यात्रा और अमेरीका और चीन का जो संयुक्त बयान निकला वह, राजनीतिक दृष्टि से यह चार बहुत महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। जहाँ तक चीन और अमेरीका के संयुक्त बयान का सवाल है और हमारे देश की और रूस की मैत्री का सवाल है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर दोनों चीजें एक ही स्तर की होतीं, एक ही तरह की होतीं, एक ही प्रकार का लाभ पहुंचाने वाली होतीं। मैं समझता हूं कि एक ओर जहां हमारी और रूस की मैत्री से हमारे मामले हल हुए हैं। जो बयान निकला है, जो हमने निर्णय लिए हैं, जो हमने कार्यवाही की है, उससे जहाँ एक दुनिया में शान्ति का पैगाम आया है, दुनिया में अमन का पैगाम आया है और दुनिया के निराश्रित और असहाय जो लोग हैं उनको सहारा देने वाली कोई चीज हुई है, उनमें आस्था जगाने वाली कोई चीज हुई है वहाँ दूसरी ओर चीन और अमेरीका के बीच जो सुलहनामा हुआ है, उसने दुनिया के बहुत से देशों में, दुनिया के बहुस से क्षेत्रों में शंकायें और खतरे पैदा कर दिये हैं। मेरी यह कामना है और मैं यह चाहता हूं कि उस संधि से भी वही परिणाम निकलें कि जो परिणाम भारत और रूस की मैत्री से और भारत और रूस के संयुक्त बयान से निकलते हैं। लेकिन उस संधि में जो बातें कही गयी हैं उनसे उस ओर इशारा नहीं होता, बल्कि उससे आशंकायें पैदा होती हैं और खतरे सामने नजर आते हैं। चीन और अमेरिका दोनों जो मिले हैं वह दो छोरों का मिलन है, अंतिम छोरों का मिलन है, दो अतिरेकों का मिलन है और इसलिए दुनिया के लोगों को इस बारे में शंका हो रही है। भारत और रूस का जो मिलन है वह समान-धर्मी लोगों का मिलन है, लेकिन चीन और अमरीका का मिलन विपरीत-धर्मी लोगों का एक साथ आना है। दुनिया में इसलिए शंका का होना स्वाभाविक है। बार-बार हम लोग देखते रहे हैं, दुनिया में ऐसे शंकालु मामले व और इस तरह की घटनायें होती रही हैं और उनसे दुनिया का अपकार हुआ है वही बात आज मुझे याद आ रही है। पता नहीं वह कहाँ तक सही होगी। मैं चाहता हूं कि वह बात सही न हो। हमारे यहां महाभारत में एक जिक्र आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र ने यह चाहा कि उनके लड़के तो मारे गये, उनके अपने लड़के अब नहीं हैं और इसलिए वे उस समय पांडवों से मिलना चाहते थे, उनका आलिंगन करना चाहते थे। उनकी यह इच्छा जान कर पाँडव एक-एक करके उनसे मिलने जाने लगे। उस समय कृष्ण ने सबको धृतराष्ट्र के पास आलिंगन के लिये जाने दिया, लेकिन भीम को नहीं जाने दिया। कृष्ण ने एक लोहे का भीम बना कर धृतराष्ट्र के पास मिलने के लिए भेज दिया और धृतराष्ट्र ने उसका आलिंगन किया। भीम के प्रति धृतराष्ट्र का असीम क्रोध था। उन्होंने ही उनके पुत्रों को मारा था धृतराष्ट्र बहुत बलशाली थे और उन्होंने अपने आलिंगन की पकड़ में उस लोहे के भीम को चूर-चूर कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि यह चीन और अमरीका का जो आलिंगन हो रहा है उसमें कौन धृतराष्ट्र साबित होगा और कौन भीम साबित होगा, लेकिन खतरा इस बात का है कि यह धृतराष्ट्र और भीम की तरह का ही आलिंगन हो रहा है। यह समय बतलायेगा कि इसमें धृतराष्ट्र कौन है और भीम कौन है।

जहाँ तक रूस का और भारत का सवाल है, मुझे प्रसन्नता होती कि यह नजदीक आने का काम और इस तरह का बयान कुछ और पहले हुआ होता। मैं यह मानता हूं कि अगर इस वक्त नहीं होता तो और ज्यादा विलम्ब हुआ होता और ऐसे वक्त पर यह काम हुआ है कि जिसके चलते हमारे दोनों देशों को ही नहीं बल्कि दुनिया के

बहुत से गरीब देशों के लिये, कमजोर मुल्कों के लिये और ऐसे लोगों के लिये जो दूसरों के खौफ खाते थे आशा का एक संदेश मिला है, निर्भयता का एक संदेश देने वाला यह हुआ है ।

हमारे बगल में जो बड़ा मुक्ति-संग्राम हुआ, जिसमें हमारे देश ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया और बंगला देश की जो मुक्ति हुई है, जो एक देश की मुक्ति हुई है वह बड़ी चीज है। लेकिन यह एकमात्र एक देश की मुक्ति नहीं है उससे बहुत बड़ी चीज है। जिन आदर्शों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर, जिन नीतियों को लेकर हमारे और बंगला देश के लोग, हमारे और बंगला देश के नौजवान, हमारे और बंगला देश के सिपाही, हमारे और बंगला देश के नेता, जनता, सरकार यह सब लड़े वह सिर्फ एक देश की आजादी ही नहीं, वह भी बड़ी चीज है, लेकिन उससे कहीं बड़ी चीजों के लिये लड़े और मैं यह मानता हूं, यह कामना करता हूं, यह चाहता हूं कि जहां बंगला देश की आजादी से एक मसला हल हुआ है, वहाँ उसके साथ ही साथ हम पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, बंगला देश के लोगों पर भी, भारतवर्ष के लोगों पर भी । मैं तो यह चाहता हूं कि बंगला देश और भारत मिल कर और रूस भी उसमें मदद कर सके तो करे, अब दुनिया में एक ऐसी राजनीति, एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बुनियाद रख सके जिसमें छोटे और बड़े, गरीब और अमीर सब देश एक समान भाव से रह सकें, एक दूसरे का डर इनका मिट सके और राजनीति में जिन मान्यताओं की, जिन मूल्यों की कमियाँ हुई हैं उनकी पुनः स्थापना करने में बंगला देश और भारत मिल कर सफल हों। यह मैं चाहता हूं। हमने कहा कि इसका बड़ा महत्व है, इसलिये नहीं कि हमें एक गुट बनाना है, हम अधिकार क्षेत्र दूसरों पर कायम करना चाहते हैं, बल्कि इसलिये कि आज दुनिया की राजनीति जिन खराबियों से पीड़ित है, जिन बुराइयों से पीड़ित है उन बुराइयों को दूर कर भारत और बंगला देश की जनता जिन ऊँचे आदर्शों को लेकर बढ़ी है और साथ काम किया है और उन आदर्शों की स्थापना कर सकें, उन्हें सारी दुनिया में, दुनिया के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक देश में फैला सकें, उनका प्रचार कर सकें तो बहुत बड़ी बात यह होगी । इसलिये बंगला देश की आजादी के बाद बंगला देश के नेताओं और हमारे देश के नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने के अलावा, राजनैतिक स्थिरता के अलावा उन्हें इस दुनिया को भी नजर अन्दाज नहीं करना चाहिये और आज की परिस्थिति में यह जिम्मेदारी बंगला देश और भारत के नेताओं और सरकार के ऊपर सबसे अधिक आ गई है। इस ओर मैं अपनी सरकार का, इस देश के लोगों का, यहाँ की पार्टियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्रीमन्, हमारे यहाँ अभी चुनाव हुआ । चुनाव जब होता है तो कुछ परिवर्तन होता है, उसका एक महत्व होता है, लेकिन इस वर्ष के चुनावों का एक विशेष महत्व है और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस चुनाव से सिर्फ एक अध्याय पूरा नहीं हुआ है इस चुनाव के चलते, सिर्फ हमारे देश के इतिहास का सिर्फ एक पन्ना नहीं बदला है, बल्कि इस चुनाव से हमने एक वृत्त पूरा किया है, एक सर्किल हमने कम्पलीट किया है, ऐसा लगता है कि वृत्त की परिधि के एक छोर से चल कर हम दूसरे छोर पर पहुँचे हैं और दोनों छोर मिल गये हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों समझता हूँ। देश की आजादी के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ सन् 1952 ई० में उसमें केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रायः प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की सरकार बनी और पंद्रह वर्षों तक लगभग यही हालत रही, 1952 ई० से लेकर 1967 ई० तक कमोबेस यही हालत रही और आज फिर पाँच वर्ष के बाद या सच पूछिये तो 1952 से बीस वर्ष के बाद हम क्या पाते हैं कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और अधिकांश प्रान्तों में भी फिर कांग्रेस की सरकारें बीस वर्षों के बाद हो गई हैं लेकिन दोनों में अन्तर है; इस बीच हमने बहुत दूरी पार की है,

[श्री गंगाशरण सिंह]

बहुत से अनुभवों से गुजरे हैं, देश अनुभवों से गुजरा है, हम सब अनुभवों से गुजरे हैं और उन अनुभवों से हमने फायदा उठाया तो इस सर्किल की पुनरावृत्ति से कुछ लाभ होगा नहीं तो नुकसान होगा। इस दृष्टि से कांग्रेस से भी और दूसरी पार्टियों के लोगों से भी जो हार गये हैं मैं कहना चाहता हूँ और अत्यन्त नम्रता-पूर्वक कांग्रेस वालों से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह सोचना चाहिये कि यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ, यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस का बहुमत है, 1952 ई० में भी बहुमत मिला था केन्द्र में मिला था और राज्यों में भी मिला था। लेकिन 15 वर्षों के भीतर देश में जो कांग्रेस-विरोधी वातावरण तैयार हुआ उसको भी उन्होंने देखा। 1967 ई० में जो कांग्रेस की हार हुई, इस सदन में जहाँ कांग्रेस बहुमत में थी यहाँ नहीं रह गई और लोक सभा में भी जहाँ कांग्रेस बहुमत में थी नहीं रह गई थी, तो पंद्रह वर्षों का जो परिणाम निकला उसको नहीं भूलना चाहिये, उससे सबक सीखना चाहिये। पंद्रह वर्षों में ऐसा इसलिये नहीं हुआ कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया था या कांग्रेस के मेम्बर कम हो गये थे कांग्रेस के प्रतिनिधि कुछ बदल गये थे, बल्कि इसलिये कि पंद्रह वर्षों में कांग्रेस की जो सरकारें थीं और वहाँ जो उनके लीडर थे उनके जो कारनामे हुए उनको जनता ने पसन्द नहीं किया। यही कारण था कि 1967 में कांग्रेस, विरोधी वातावरण देश के अधिकांश हिस्सों में चला। जो वायदे कांग्रेस ने किए थे वह पूरे नहीं किए, जो गड़बड़ियाँ उन्होंने की, उन गड़बड़ियों से जनता नाराज हुई। इसी लिए आप पाइएगा कि जनता का कांग्रेस के प्रति, चाहे जो भी कारण हो रूख में परिवर्तन हुआ। वह आजादी के लिए लड़ने वाली संस्था थी, आजादी लाने वाली संस्था थी, इस कारण ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के प्रति वफादार थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों के प्रति वफादार नहीं थे। यह एक ओर जहाँ लोगों की बुद्धि की मैच्योरिटी का द्योतक है, वहाँ इस बात का भी द्योतक है कि वे भावनाओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन सिर्फ भावनाओं में बहते नहीं हैं। इस-लिए पन्द्रह वर्षों के अंदर जो कार्यवाहियाँ हुईं, उन्होंने देश में एक कांग्रेस विरोधी वातावरण तैयार किया। लेकिन कांग्रेस ने जितना विरोध अर्जन किया था पन्द्रह वर्षों में, हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस विरोधी दल के साथियों ने पाँच वर्ष से कम समय में वह विरोध अर्जन कर लिया है। इसी लिए आज जो फिर से कांग्रेस की जीत हुई है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से कारण हैं, बहुत सी चीजें है। मैं यह भी मानता हूं कि बंगला देश की मुक्ति का भी असर पड़ा है, प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व का, नेतृत्व का असर पड़ा है। मैं यह भी मानता हूं कि साधनों का भी असर पड़ा है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इन चार-पाँच वर्षों में, जो दूसरी पार्टियाँ थीं, उन्होंने जिस तरह से सरकारों को चलाया उससे भी जनता खुश नहीं थी, यह भी एक बड़ा कारण रहा है, जिसके चलते कांग्रेस को वोट मिला है। जो हार गए हैं उनसे मैं यह कहना चाहूंगा—सिर्फ लाँछन लगाने से, सिर्फ दोष लगाने से, सिर्फ गलतियाँ दिखलाने से काम नहीं चलेगा वह गल-तियाँ भी हो सकती हैं और हुई हैं, उन गलतियों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए—क्षमा करने से काम नहीं चलेगा। गत चुनाव के दौरान, चूंकि चुनाव के काम में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और कई कामों से, मुझे देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जाने का मौका मिला, तो मैंने यह देखा कि आज एक पार्टी दूसरी पार्टी पर जो आक्षेप लगा रही है। वह काम सभी के पार्टी के लोगों ने किया है। भले ही पार्टियाँ ऊंची-ऊंची बातें करें, लेकिन किसी पार्टी का आदमी ऐसा नहीं है जिसने स्वयं वही गलती नहीं की है, जिसके लिए दूसरे पर आरोप लगाती है। फर्क सिर्फ अनुपात का है, किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया वह बात दूसरी है।

जहाँ तक पोलिंग बूथ्स के घिराव का प्रश्न है, पोलिंग बूथ में विरोधियों को नहीं जाने देने का प्रश्न है, अपने गांव से बाहर नहीं निकलने देने का प्रश्न है, वोटरों के लिए सवारी लाने का

प्रश्न है, वोटरों को पैसा देने का प्रश्न है, वोटरों को जाँत-पाँत के नाम पर भड़काने का प्रश्न है, प्रायः कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जो अपवाद हो सकते हैं, अधिकांश ने इसका फायदा उठाया और इसलिए कोई आदमी नहीं कह सकता अमुक पार्टी इसकी गुनहगार है, अमुक पार्टी दूध की धोयी है, उसने अनुचित लाभ नहीं उठाया। आज कोई पार्टी यह नहीं कह सकती कि अमुक पार्टी के लोगों ने इन हथ-कंडों से लाभ उठाया, दूसरी पार्टीयों ने लाभ नहीं उठाया—अगर किसी ने लाभ नहीं उठाया तो इसलिए नहीं कि लाभ उठाने का इरादा नहीं था, बल्कि लाभ उठाने की क्षमता नहीं थी, साधन नहीं था, जरिया नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी—इसलिए नहीं कि स्वस्थ मान्यताओं के प्रति उनके कार्यकर्त्ताओं की धारणाएं थीं, उन मान्यताओं के प्रति उनकी आस्था थी या इन मान्यताओं के लिए वे हार बर्दाश्त करने को तैयार थे, इसलिए यह काम नहीं किया। बल्कि लाचारी के चलते उतने या उस प्रकार के गलत काम नहीं कर सके।

जहाँ एक ओर जीत की खुशी हो, जहाँ एक ओर हारने का गम हो वहां साथ-साथ यह भी सोचना चाहिए हारने वालों को भी जीतने वालों को भी और इस चुनाव के परिणामों का विचार करके अपनी-अपनी गलतियाँ सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो कहीं मैंने पढ़ा था कि क्रांतिकारियों की कई परिभाषाओं में, एक परिभाषा मुझको बार-बार याद आती है कि क्रांतिकारी असली में वह है जो हर गलती से सबक सीखता है, जो क्रांतिकारी अपनी गलती से सबक नहीं सीखता है वह क्रांतिकारी नहीं है, वह पुराणपंथी है, पुरानी चीजों की लीक को पीटने वाला व्यक्ति है। इसलिए अगर आप चाहते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सही में कार्य क्रांतिकारी बनें तो अपनी गलतियों से सबक लें। इसलिए जो पार्टियां चाहती हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बनना वे दूसरों की आलोचना तो करें, लेकिन आलोचना करने के साथ-साथ मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि जो गलतियाँ उन्होंने और दूसरे लोगों ने की हैं उनसे सबक सीखें और उनसे ऊपर उठ कर विचार करें। साथ ही साथ यह भी सोचना चाहिए कि अधिकांश पार्टियों को मौका मिला कहीं न कहीं सरकार में अधिकार में जाने का। सबको तो नहीं लेकिन अधिकांश पार्टियों को किसी न किसी प्रान्त में जाने का मौका मिला। लेकिन क्या हुआ, वहाँ सरकार में जाने के बाद थोड़े ही दिनों के भीतर जो बहुत सी विरोधी पार्टियाँ थी, उन्होंने अपने खिलाफ वातावरण बना लिया, अपने ही खिलाफ जनता को कर लिया। पन्द्रह वर्षों में कांग्रेस ने जितने पाप कमाए, कुछ लोगों ने वर्ष या छः महीने में उतना कमा लिया। यह हाल रहा। यही कारण है कि आज 5 वर्षों के बाद आज जनता फिर कांग्रेस के पास जाना चाहती है; क्योंकि इन पाँच वर्षों में उसने दूसरों की करनी देख ली। इसलिए अब दोनों के लिए सीखने का सवाल है। इसी तरह से कांग्रेस को भी सीखना चाहिए जो जीत कर आए हैं, उन्हें भी सीखना चाहिये।

लेकिन साथ ही साथ इस बात पर गौर करना चाहिए—मैंने पिछली बार भी कहा था, अब फिर कहता हूं—ये चुनाव जितने खर्चीले हो रहे हैं, इन चुनावों में जितने साधन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, इन चुनावों का जो तरीका हो रहा है, इन हालत में किसी भी पार्टी के वर्कर को लीजिए वह अपने या पार्टी के बल पर चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर सफाई से इस मसले पर विचर किया जाए—तो मेरा खयाल है कि हम सभी एक राय के होंगे कि आज एक साधारण, पुराने ढंग के कार्यकर्त्ता के लिए जिसका सारा जीवन सार्वजनिक काम में गुजरता है और जिसकी आमदनी का दूसरा जरिया नहीं है, उसके लिए आज का चुनाव लड़ सकना सम्भव नहीं है, उसके लिए आज का चुनाव लड़ना असम्भव हो गया है। या तो आपके पास खुद अपना पैसा हो या थैली आपकी पीठ पर हो तभी चुनाव लड़ सकते हैं।

बंगला देश का सारा गुडविल था, इन्दिरा जी का नेतृत्व था, सारी चीजें थीं। लेकिन

[श्री गंगाशरण सिंह]

कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि इन्दिरा जी के नेतृत्व और बंगला देश की मुक्ति के श्रेय की पूंजी के बावजूद क्या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार कानून द्वारा निश्चित अधिकतम राशी के भीतर खर्च का चुनाव जीत सका है। क्या 1961 के चुनाव में जो भावना थी उसका कहीं पता इस चुनाव में था।

इसलिए जहां हारने वाले लोगों से कहना चाहता हूं वहां मैं कांग्रेस वालों से भी कहना चाहता हूं कि इस जीत की खुशी में यह बात मत भूलिये कि आप इस चुनाव को ज्यादा खर्चीला बना रहे हैं और चुनाव के कार्यकर्ताओं के लिए असाध्य बना रहे हैं, साध्य नहीं बना रहे हैं। प्रत्येक पार्टी कांग्रेस वाले अपनी जीत पर खुश हैं, जहां विरोधी दल वाले अपनी हार पर निराश हैं, लेकिन दोनों दलों के कार्यकर्त्ताओं के बीच आज मायूसी है। आज उनमें चिंतन चल रहा है, आज परेशानी हो रही है; क्योंकि जाँत पात के अलावा, घेराव के अलावा, प्रान्तीयता के अलावा, दूसरी बुरी चीजों के अलावा पैसे का प्रश्न भी चुनाव में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और जब हम इतना खर्च करके जनता के सामने जाते हैं, इमानदारी की बात कहते हैं, तो क्या वह ईमानदारी के सम्बन्ध में हमारी बात को सुनेगी।

चुनाव के कानून में लिखा हुआ है कि एक चुनाव में इतनी रकम से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिये। हमारे चुनाव क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है कि उसके उम्मीदवार ने 50 हजार रुपया तक खर्च किया है और उसके बाद भी हम जनता को उसकी नैतिकता की शिक्षा दें, मौरेलिटी की तालीम दें, सो क्या वह मौरेलिटी और शिक्षा की बात को सुनेगा जिस आदमी को पैसा देकर हमने उसका वोट लिया है। आप जानते हैं कि जितना चुनाव में खर्च करने के लिए कहा गया है उससे ज्यादा खर्च किया जाता है। उसके बाद भी हमारा क्या मुंह रह जाता है कि हम यहाँ पर बैठ कर कहें कि तुम नैतिकता की बात करो। इसलिए जहाँ एक ओर राजनीतिक जीत हुई हैं वहाँ मैं कांग्रेस के लोगों से और विशेष कर प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी इस मामले में बहुत बढ़ गई है। आज राजनैतिक नेतृत्व का पूरा का पूरा भार उनके हाथों में आ गया है, केन्द्र में और प्रान्तों में कांग्रेस और प्रधान मंत्री के हाथ में सरकार आ गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनैतिक नेतृत्व के साथ-साथ आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस देश में नैतिक नेतृत्व पैदा किया जाय। जब तक मोरल लीडरशिप नैतिक नेतृत्व नहीं होगा तब तक जो हमारी राजनीतिक जीत होगी, वह क्षणिक और अस्थायी होगी और उससे इस देश का आगे चल कर विशेष फायदा होने वाला नहीं है। केवल पार्टियाँ फायदे में रहें और जनता को फायदा न हो, कोई पार्टी जीत कर आये और उसकी कथनी और करनी में अन्तर हो तथा जो पार्टी जीत कर आये वह अपने वचनों को कारगर न कर सके तो उससे जनता में नैतिक गिराव आयेगा। सिर्फ सरकारी बल पर कोई काम नहीं होगा जब तक कि जनता का मनोबल नहीं जगाया जायेगा और जनता का सहयोग प्राप्त नहीं किया जायेगा। तब तक हमारे देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

आज हमारे देश में अनैतिकता की धारा चल रही है और उसको रोक कर जब तक हम जनता में नैतिकता का बल नहीं उभारेंगे तब तक मेरा खयाल है कि चाहे हम देश में कितने ही प्लान क्यों न बनायें उससे कुछ नहीं होगा। हिन्दुस्तान की जनता का तो यह हाल है कि कांग्रेस वाले आये, 15 साल तक वे रहे, अपोजीशन की पार्टियाँ आईं, चार पाँच साल तक वे रहीं भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अधिकार में रही। मैं उनको जानता हूं क्योंकि मेरा उनके साथ निकट का सम्बन्ध रहा और कुछ सरकारों को बनवाने में मेरा थोड़ा हाथ भी रहा। लेकिन आज मैं उन निराश व्यक्तियों में से हूं जैसा इकबाल ने कहा :

"दरदे इन्साँ अब तलक भी तालिब दरमाँ रहा" ई जनाब आते रहे ओ आँ जनाब आते

रहे। मनुष्यता का जो दर्द है, जो कष्ट है, वह आज भी दवा की प्रतीक्षा कर रहा है।

यह सरकार आई, वह सरकार आई, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि एक बार हम फिर इस बात का सिंहावलोकन करें कि चुनाव में जो जीत हुई है वह किन कारणों से हुई है। क्या कोई ऐसा मध्यम रास्ता, ऐसा कोई पुल बन सकता है या नहीं जो भिन्न-भिन्न विचारों के लोगों को भी एक रस्सी में बांध सके और देश के उत्थान के काम में जो खराबी आ गई है उसको दूर करने में सब विचार वाले, सब दल वाले और सभी लोग शामिल होकर उस खराबी को दूर कर सकें। लेकिन खतरा इस बात का है कि इन 20 वर्षों के बाद जो एक नया अध्याय शुरू हुआ है, एक नया वृत्त शुरू हुआ है और उस वृत्त और उस नये अध्याय से जो लाभ जनता को होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं इस ओर ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पार्टियों के चुनाव घोषणा-पत्र पर गौर किया जाय। आपको शब्दों में बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा, बहुत कम फर्क है। वही बात है, शब्द वहीं हैं, लेकिन जैसे पुराने जमाने से हर मजहब में होता है, जो मजहब का पैगम्बर होता है, ऋषि होता है, वह जो कुछ कहता है वह वेद वाक्य होता है और हर धर्म और सम्प्रदाय के अलग-अलग लोग उसके अपने अलग-अलग माने लगाते हैं। वही हालत आज राजनीति की भी हो गई है। राजनीति की शब्दावली में आज हर आदमी समाजवाद की चर्चा करता है, हर आदमी सूत्र रूप में वही बात कहता है, लेकिन जब व्यवहार में लाता है तो बात एक दूसरे के प्रतिकूल मालूम होती है। मैं थोड़े में यही कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों ने, जनता की आवाज ने और जनता की मांग ने आज राजनीतिक पार्टियों तथा राजनैतिक लोगों को मजबूर कर दिया है कि कम से कम वे सूत्र रूप में एक बात बोलें उनका खयाल कर उनके व्यवहार में एकता और समानता हो। मैं समझता हूं आज देश में उसके अधिकांश कामों में तटस्थता से विचार किया जाय तो भिन्न-भिन्न पार्टियों में मतभेद की बहुत गुंजायश नहीं हो सकती है।

जैसे आज जितनी घूसखोरी है उसको हटाओ, आज जनता के पास रोटी पहुंचाओ, आज जनता को जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनको दूर करो, आज जनता के पास घर नहीं है, घर दो। उन कामों के करने के तरीके में फर्क होगा। लेकिन वह भी मैं समझता हूं कि थोड़ा होगा। क्योंकि आज कोई यह नहीं कह सकता कि देश में ऊंच-नीच रहना चाहिए। चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो। जब सारी चीजों के बारे में हम एक बात कहते हैं तब व्यवहार में फर्क क्यों। इसलिए आज की परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि एक नैतिक नैतृत्व, नैतिक आचरण, नैतिक हवा देश में ऐसी होनी चाहिए कि राजनीति उसके साये में चल सके, जो राजनीति को बल प्रदान कर सके या राजनीति को मार्ग दर्शन दे सके या अगर राजनीति गलत रास्ते पर चलती है तो नदी के दोनों कगारों की तरह उसे रोक कर सही रास्ते पर चला सकें, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह मौका जो हमें 20 वर्षों के बाद मिला है हमने खो दिया तो निकट भविष्य में ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है।

हमारा देश एक विरोधाभास का नमूना है। एक ओर आप पाएंगे कि अन्न में हम स्वावलम्बी हो गए हैं, आंकड़ों से तो हो गए हैं, पैदावार से भी हो गए हों, लेकिन आज भी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जाइए तो स्वावलम्बिता का पता गरीबों के घरों में नहीं चलता। अन्न के मामले में हम स्वावलम्बी हो गये हैं, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ गई है और बहुत-सी चीजों की कीमत बढ़ती चली जा रही है। आज कपड़े का सवाल है। ऐसे लोग हैं जिनको मोटा कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर जाइए तो बाजार फैशनेबिल कपड़ों से भरे पड़े हैं जिनके पहनने वाले कितने प्रतिशत होंगे मैं नहीं जानता। मैं समझता हूं कि अगर असमानता को दूर करना है, राजनीतिक

[श्री गंगाशरण सिंह]

स्तर पर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर पर समानता लानी है तो जो यह विरोधाभास है, अतिरेकता है, एक्स्ट्रीमिटी है इसको कम करना चाहिए, दूर करना चाहिए, तभी समानता होगी, नहीं तो जब तक अतिरेकता रहेगी, एक्स्ट्रीमिज्म रहेगा तब तक समानता नहीं आ सकती। समानता डेमोक्रेसी की तरह, जनतंत्र की तरह मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग है इसमें अतिरेक की गुंजाइस नहीं होती। जबान से हम समानता की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में अतिरेकता की बात।

राष्ट्रपति के भाषण में जो बातें कही गई हैं वे बातें अच्छी हैं, वे अगर कुछ और तफसील में कही जातीं तो अच्छा होता लेकिन उसकी शायद गुंजाइश नहीं थीं, वह भाषण 35 मिनट का था और बड़ा हो जाता। वह भाषण सूत्र के रूप में है जैसे उपनिषद् के सूत्र हैं या वैदमंत्र के सूत्र हैं, उनकी चाहे जो व्याख्या हम कर लें लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी वैसी व्याख्या न करे जैसी अब तक करती रही है, उनकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो जनता समझ सके।

मैं यह मानता हूं कि उत्पादन हुआ है, लेकिन उसके वितरण के तरीके में कुछ ऐसी खामी है जिसको दूर किए बिना बढ़ा हुआ उत्पादन जनता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए उत्पादन बढ़ने के साथ आज एक बार फिर हमको उसके वितरण के तरीके पर विचार करना चाहिए और वह खाई कहां है जिसके बदले उत्पादन बीच में खप जाता है, आम जनता तक नहीं पहुंच पाता, इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरा खयाल था राष्ट्रपति को अपने भाषण में उत्पादन और प्रोडक्शन की बात करने के साथ मेथड और पद्धति के सम्बन्ध में विशेष चर्चा करनी चाहिए थी और वह खाई कहां है, कहां वह गड़बड़ होती है उसकी ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहिए था। उत्पादन हुआ है लेकिन उत्पादन होने के बावजूद जनता को जितना लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, बीच में जो गड़बड़ी है उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, एक कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट का भी वही हाल हुआ जैसा और कमेटियों का होता है कि कमेटी बनी है काफी दिनों तक काम करती है, लाखों खर्च होता है और फिर उसकी रिपोर्ट दाखिल दफ्तर हो जाती है। आज मुझे यही कहना है कि 20 वर्षों के बाद विरोधी पार्टियों और कांग्रेस को नए सिरे से सोच कर आगे कदम उठाने की जरूरत है, अब तक के रास्ते कारगर साबित नहीं हुए हैं, नए रास्ते अख्तियार करने की जरूरत है। यही मेरा उनसे निवेदन है।

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair]

श्री डी० के० पटेल (गुजरात) : श्रीमन्, माननीय राष्ट्रपति के समूचे अभिभाषण में शिक्षा का जो प्रश्न है, जो समस्याएं हैं, उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। किसी भी देश के विकास के लिए, देश के जनतंत्र के विकास के लिए, शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। लोगों की शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी है। सारे अभिभाषण को दुबारा में देखा गया, लेकिन शिक्षा का उल्लेख कहीं पर नहीं मिला। हमारा जो शिक्षा का आज का सिस्टम है, जो ढांचा है, वह पुराना ढांचा है, अंग्रेजों का दिया हुआ ढांचा है, उसमें अपेक्षित परिवर्तन आज तक हम नहीं कर पाये। परिणामत: हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों से हजारों की संख्या में स्नातक बाहर आते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता, बेरोजगारी हमारे सामने खड़ी है। तो चाहिए तो यह कि जब कांग्रेस विभिन्न राज्यों की सरकारों में बड़े भारी प्रभाव में आई है तो वह शिक्षा के प्रश्न को प्राथमिकता देने की कोशिश करे। वैसे आज जो शिक्षा है वह एक पुरानी परिपाटी पर चल रही है। सरकार को सर्वे कराना चाहिए कि इस देश को कितने मैनेजेरियल स्टाफ की जरूरत है, कितने आर्टिजन्स की जरूरत है, कितने टेक्नीशिएंस की जरूरत है, कितने इंजीनियर्स की जरूरत है, कितने डाक्टर्स की जरूरत है। अगर एक स्पष्ट चित्र सरकार के सामने नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। शिक्षार्थी की अभिरुचि का

खयाल करके शिक्षार्थियों को विभिन्न शिक्षा की शाखाओं में भेजने चाहियें। अगर यह काम नहीं हुआ तो हो सकता है कि हम बातें करेंगे बेरोजगारी मिटाने की, गरीबी हटाने की, लेकिन इस देश में एक बड़ी फौज बेरोजगारों की बढ़ती जायगी। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोटी कमाने का हो नहीं सकता, शिक्षा का उद्देश्य केवल कोई छोटे बड़े उद्योग की तालीम शिक्षार्थी को दे देना हो नहीं सकता। शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है और बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए नैतिकता उसमें आनी चाहिये। विश्व के विभिन्न धर्मों के प्रमुख तत्वों को तुलनात्मक रूप से शिक्षार्थियों के सामने रखना चाहिये ताकि देश में जो आज एक नैतिक ह्रास, सामाजिक एवं राजकीय मूल्यों में जो एक प्रकार की गिरावट आई है, अधःपतन हुआ है, उसको रोकने के लिये हम काबिल हो पायें। आज देश के अन्दर वे नैतिक मूल्य रहे नहीं जो कि होने चाहिये। जो देश के प्रतिनिधि चुने गये वे भी आज बिकते हैं, पैसों से बिकते हैं, प्रजातंत्र शासन प्रणाली को तोड़ने के लिए उन्हें लालच दिया जाता है, सरकारें गिराई जाती हैं। तो शिक्षा में अगर नैतिकता का हम प्रवेश नहीं करायेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में हम नई रोशनी नहीं देख पायेंगे, नया चरित्र, नये संस्कार नहीं देख पायेंगे।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में ऐसे लोगों को जुटाना चाहिए, जिनकी शिक्षा में गति हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन करने हों वे ऐसे लोगों के द्वारा होने चाहिएँ जो शिक्षा के ज्ञाता हों, अच्छे शिक्षा शास्त्री हों। आज तो ऐसा है कि राजनीति के अखाड़े में जो बड़ा मल्ल है उसको हम शिक्षा के स्थान पर बिठा देते हैं। तो इस देश में जो वास्तव में शिक्षा के ज्ञाता हैं उनके हाथ में शिक्षा का काम सौंपा जाय। न्याय तंत्र जिस तरह से हमने मुक्त रखा है उसी तरह से हिन्दुस्तान में शिक्षा को भी मुक्त रखा जाय। राजकीय नेताओं के अथवा राजकीय अधिकारियों के शिकंजों में, उनके चंगुल में हमारे शिक्षा विभाग को नहीं जाना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक और बात की कमी महसूस हुई और वह यह है कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो हरिजन समाज है, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई बात उसमें नहीं मिली। युगों से जो बदनसीब हैं, सबसे पीछे हैं, उनको आगे लाने का कोई कार्यक्रम उसमें नहीं मिलता। मैं यह अभियोग लगाऊंगा कि इस देश में 25 साल से कांग्रेस की हकूमत रही और स्थिर सरकार भी इस देश में थी, लेकिन पिछड़ी जातियों को संविधान में जो सुविधायें प्राप्त हैं वह भी हम उनको नहीं पहुंचा सके। यही नहीं, उन के लिए जो सुरक्षित स्थान हैं, उनको वहाँ से हटाने का कार्यक्रम भी चलता रहा। तो मैं आशा करता हूं कि पिछड़ी जातियों की जो जनसंख्या है उसके अनुपात से उनके विकास के लिए बजट की कुल राशि में से हिस्सा अलग कर दिया जाय।

यह कहा जाता है और बड़े-बड़े पोस्टरों में पढ़ा जाता है कि कांग्रेस को वोट इसलिए दो कि देश में लोकशाही जमे, लेकिन इस देश में पिछले 5,6 महीनों में, पिछले एक साल में लोकशाही की जो प्रणाली है उसको भंग करने का ज्यादा अभियोग अगर किसी पर लगाया जा सकता है तो वह इंदिरा जी की सरकार पर ही लगाया जा सकता है और आप मुझे यह कहने का मौका दीजिए कि मैं जो यहाँ पर आ पाया हूं उसका एक कारण यही था कि गुजरात में लोग पक्ष परिवर्तन करते थे। उसका एक वायदा मुझे भी मिला। मुझे भी उसका कुछ लाभ मिला और इसी लिए अकस्मात् घटनावश मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूं। मैं उसका एक प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। मैंने देखा कि रुपयों की थैली लेकर विधान सभा के सदस्य इधर से उधर होते थे और इस तरह लोक शासन तंत्र प्रणाली का ह्रास होता था। फिर भी कांग्रेस लोकशाही की बात करती रही और देश ने उसको कुछ श्रद्धा और आशा के साथ इन्दिरा जी के पक्ष से अपना बहुमत आज दिया है, तो मैं विरोधी दल में होते हुए भी यह आशा करूंगा कि अभी से इस देश

[श्री डी० के० पटेल]

में जो लोकशाही शासन और उनकी प्रणाली को भंग करने की प्रवृत्ति है उसको अब तो रुकना चाहिए । कुछ लोग इधर-उधर की बात करते हैं कि उधर जाने से कुछ फायदा होगा, उनको लेने का आप का कार्यक्रम अब बंद होना चाहिए ।

अंत में एक बात और कहनी है कि गुजरात में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि वहाँ के जो साम्यवादी नेता हैं, वे आदिवासी स्वायत्त राज्य की घोषणा अपने पत्र-पत्रिकाओं में करते रहते हैं । वहाँ कुछ ऐसे नेता भी हैं, आदिवासियों के, जो सती-पती-कल्ट के नाम पर हमारे संविधान को नहीं मानते, कॉस्टीट्यूशन में श्रद्धा नहीं रखते और वे ऐसी बातें करते हैं । उसका कारण क्या है ? उन पिछड़ी जातियों के लिए जो कुछ गुजरात में होना चाहिए था वह नहीं हुआ और यहाँ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सुझाव आये हैं उसमें मैंने देखा कि बिहार में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं ।

तो मैं चाहूंगा और सरकार भी दावा करती है कि हम इस देश में जो गरीब हैं, पिछड़ी हुई जातियों के लोग हैं उनके लिए कुछ करेंगे तो वास्तव में बहुत बड़ा मौका मिला है, जिसका वह उपयोग करें । यही मेरी प्रार्थना है ।

4 P.M.

SHRI SITARAM JAIPURIA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very happy to associate myself with the Motion of Thanks by our revered Rashtrapatiji. He being the first citizen of the country, it is but necessary that we all give him due respect and dignity that he deserves not only because of the high office but because of the vision with which he has presented his Presidential Address at the joint sitting of Parliament. There is, however, one thing which strikes to me, Mr. Vice-Chairman. While the Address notes the hopes and aspirations of the people, but if the past performance is any indication, I am constrained to say that the President's Address does not in any way bring to light those particular spots on which the failure of the Government, not because of their intentions but because of the actions, has proved beyond doubt. Certainly, the image of India has improved considerably not only on the democratic field but also on the international field, and I would like to falicitate our Prime Minister for the great position that she has achieved in the international world, and 1 may say that she has become a solitary national hero today. Nevertheless we cannot forget that it is not only the image of the Prime Minister which is reflected in the image of the country no doubt, it is the country's own prosperity which should ultimately reflect the country's image all over the world. It is light in the sun which reflects all over the universe and not the light of the universe itself which reflects in the sun. It is for tliat reason, because one is complementary to the other, that I would like to devote more time to the national aspects of our country's present situation and then I am quite certain that the international image will itself take care to a large extent.

One of the finest things that has happened in the recent conflict lias been that for the first time in the world history, Mr. Vice-Chairman, two great countries, the United States and China have been completely isolated from the friends of their own circle. On the one side* the United States of America has been isolated; from countries like Britain, Germany, France and many others, on the other China has also been isolated from the other countries like Poland, Czechoslovakia etc. And when it is said that there is always friendship between those two nations or individuals who are both solitary, it is no wonder that they should both join hands together. But this is a thing which should not disturb us. In fact, if the joining of the hands is in the larger interest of the world peace, every one of us should welcome it,

I would like to say when the President in his Address, in paragraph 4, said, "When I addressed you last year, 1 called upon you to give undivided attention to economic and social transformation." I would like to know, since the last Address of the President, what exact attention has been paid to the economic and social transformation. To my mind, it has been more of a lip expression than the actual work that has been done in the field. Has the prosperity of the country increased? If the prosperity of the country has not in-

creased in spite of whatever we may try to prove, repetitions of an untruth a hundred times cannot make one truth. I would, therefore, say that this social transformation has not been achieved because the economic prosperity of the country has not developed as well as we would like it to be.

In fact, the President, further said that the peace on our borders is still uneasy and vigilance cannot be relaxed. True, vigilance cannot be relaxed. But the vigilance can also be maintained, Mr. Vice-Chairman, if the prosperity of the country increases in all different aspects of the country's economy. Economy will bring political stability and political stability and economic stability together will bring prosperity to the country, and if the prosperity is to the country, it is to the whole nation, to every citizen of this country. The President has very rightly noted that "the slow progress in the industrial sector, however, has been causing concern." If this one particular aspect which is causing concern could have been taken care of, I for one am convinced that most of the problems would have been solved.

Let us now look to the industrial licensing policy. There are some extremists here who say that the licensing policy should be completely abolished while there are others who feel that the licensing policy is the only panacea for all the problems. I feel that while the industrial licensing policy to a certain extent has been a check on the development of industries, on the other side, the licensing policy has also acted as a fillip to a few and has stopped the progress for many others. Instances are not lacking where licences have been taken away by many big houses and individuals, individuals who have never been in business, individuals who do not know what exactly business is. Instances are also not lacking where those very persons either have sold those licences to others for some pecuniary gain or they have not utilised them, thus blocking the capacity for other entrepreneurs who would have been able to establish industries within a short time. In fact, many times many of the industries suffer because the basic raw material for those industries depends on other industries. And if some of them belong to the public sector. I am not in any way undermining them; I only say it with all respect—then the public sector undertakings get away with a nicely drafted letter, forgetting about the consequences which it will have on the entire economy of the country. It is in this context that I say that the licensing policy and system which has come to stay in this country and which it is difficult to abolish in the circumstances that are there now, should be modified in such a manner that it does not act as a hindrance but acts as a tool of further development. I would submit that if any person has taken a licence and has not implemented it within a certain period of time, the Government should take care that licences are not given in future to those persons. That would be one way of ensuring that the rated capacities are not affected. There are instances also where people have got licence for a certain capacity but that capacity has been far exceeded with the Government looking on as a silent spectator. Instances are also not lacking where it has taken nearly five years, a full Plan period, for the Government to decide whether the licence for a particular item should be given or not. And, Mr. Vice-Chairman, it has come to this stage that everybody is running from one Ministry to another in order somehow to get over the problems that they are facing. In this context, I have my own doubts if the *artik swaraj* which our President has mentioned in his Address and which everyone of us wants to achieve, can ever be achieved. *Artik swaraj* may not mean only development of industries, but *artik swaraj* naturally means that everybody should be free from the problems of earning their bread and they should also be useful citizens of the country who can be engaged in useful occupations so that they can maintain themselves and their families. What is happening these days? I am particularly worried that the intelligentisia of our country, especially the middle class people, are the worst hit. We have seen many Budgets and this evening we are going to hear another Budget. But if the prievious Budgets are any indication, the people in the income group Rs. 2,000 to Rs. 3,000 will be the worst hit. The intelligentsia is asked to engage themselves only in earning their bread and butter and in maintaining their families and they are denied the opportunity, which they rightly deserve and for which they have capacity in their mind, to put the country on the right road and to tell the people how the country should behave. Instead they are asked not to go on these lines but only to take care of their own families and somehow to retain their reputation and status to live.

[Shri Sitaram Jaipuria]

I have my doubts if any country in the world has ever progressed without the progress of *thi* intelligentsia class, the middle class and the upper middle class, who are supposed to be the backbone of the entire country. Even if large industries are taken into consideration, it is a great misnomer. If a corporation is headed by a cjrtain individual, it does not belong to him. It belongs to thousands and thousands of shareholders. When the Government takes over a concern, the Government pleads that it is utilising it for the public benefit. Let me put it straight to the Government. Government budget, Government income, always depends on the expenditure. But in the case of a private individual or a private company, his or its expenditure will depend on the income that he derives. And if it is taken into consideration that a public corporation or an institution does not belong to him, is not his paternal property but the property of the nation, of the people because it is the people who make the nation, then, to think that he owns that particular concern or enterprise is the biggest misnomer. When many of my friends who pose as extreme socialists say that the policies of the Government have made the rich richer and the poor poorer I quite agree with them to a very, very, great extent. And why? The simple fact is it is the corporations or the institutions which have grown poorer. It is their use of money, it is their resources which are being dried up rather than that of an individual because an individual's income cannot increase, it will be the same. We have to make both ends meet. If somebody is dishonest, it can apply to every section of the population, whether it is a worker or an industrialist or a politician or a Government officer. Anybody who wants to be dishonest has plenty of options open to him. But that does not necessarily mean that everybody is dishonest. What we have to see is that people are not made to be dishonest. Laws are made for the average man. They are not made for angels and rogues. Angels do not need them and rogues do not care for them. In such circumstances, if laws are made for average people, I do feel that tke country will be on a better ground to stand and progress. There is this biggest misfortune of the industrial and trading class in this country. Take, for instances, contributions to the National Defence Fund during the war. Can anyone say that the industry, the trading community, has not contributed to the National Defence Fund? They have contributed to it. It may be that they have not contributed as much as you expected them to. It may be that some of them have not contributed. But they have, by and large, contributed. But just to take a particular section, a "particular class, and to point out that the entire class does not serve the community, is, I think, the biggest misfortune in this country. Even during the war period if supplies had not been maintained by the industry and trade as a whole, the Generals, our jawans, and all other persons who were on the battlefront would have been starved for want of them. True, there are black sheep in every class, in every community. But that does not necessarily mean that one person should be picked up in the entire class and then the entire class should be condemned. You either punish the particular person for the wrong thing or you reward him for the good thing. That is the only way by which you can convert the individual into a better person for the welfare of the country. But if every person is supposed to hear day in and day out, I am sure even the best person will have the tendency to think, why should I be a better one? He will behave in a manner that will suit him most. I would most humbly urge on the President and the Government of India because they have mentioned that industrial peace is the sheet-anchor for the country's progress and the President has even said that there should be a five-year moratorium on strikes and lock-outs in the country. But what we see in the country is if workers go on strike, they are told, you should not have done it, but any way, now that you have already struck work, well, something will be done. But if an employer does a lock- out, he is told, you will be punished under the law. You say it because there it is a single individual. I do not mind an employer being punished if he has broken the law. But the law should apply everywhere.

The Union persons are from outside the industry. They are not in the industry itself. And such people are looking after the welfare of the workers. If the workers strike, their pockets are not affected. I would, therefore, urge that the trade union movement in this country should not only be rearranged, but should be adjusted in a manner that the trade unions should be run by persons who actually are working in the industry and not by those persons who are inducted from outside the industry. This is in the interests of both the

workers and the industry. I am quite convinced that the present arrangement is not going to help either sector and will be a great loss to the country and to the industry in which they work.

I would like to say that clothing, housing and food are the most essential items to make a man happy in this world and if these are provided every citizen of this country will feel proud. But while great attention is being paid to programmes for providing water, electricity and credit to farmers and they have made headway and while credit from public and co-operative institutions is flowing into development of irrigation, particularly ground water resources, I have to say one thing. I am for all these. In one of the sugar factories with which I am connected, more than 80,000 growers are attached to it. I know fairly well that the tubewells were being constructed. But most of them have not been completed. Such of them as have been completed are out of order because there is no electric connection to make the motors work. And power is not being utilised in such of them as are working because farmers cannot afford to utilise power for the simple reason that the electric charges levied by the Electricity Board at the instance of the Central Government are so high that they consider them beyond their reach. What I want to say is that if the money is flowing, it should not be wasted. Let the flow be in a manner that the growth of the region and the agricultural produce will be substantial.

Similarly, in the matter of clothing. The President has referred to the Bangla Desh problem and every citizen of the country feels proud of the way in which it has been tackled. It is one of the best things that could have happened to any country. It has more or less solved the problem that we have been facing and because of that today our heads are high. But prices are going up. Prices won't come down because of government measures alone. It is not like Napoleon telling River Nile Thus far and no ferther. It is mainly because the purchasing power of the people has gone down to such an extent that any rise in price is considered by them out of their reach and means. Why have prices gone up? One of the most * important factors is the excise duty that has been levied. The people at large do not exactly know what percentage of the price goes as excise duty. There are some items where 60 or 70 per cent of the cost goes as excise duty. Excise duty is necessary. Taxation is essential in a civilised society. But the people who pay the tax or excise duty are absolutely entitled to know how much of the tax is properly utilised. If the taxes are properly utilised, in the long run self-generated economy based on those taxes can create a condition by which the citizens of tomorrow in particular will not have to go on paying tax. If that condition is likely to be achieved, the present generation would not mind paying higher taxes. In this context, I would most humbly suggest that government must reorient their tax structure in such a way that the citizens of today and tomorrow have the confidence that the taxes that they are paying today will be utilised properly so that they will not be asked to make any more sacrifices in this direction.

There is no doubt that the President's Address mentions that nothing great has ever been achieved without consistent endeavour and sacrifice.

And, Sir, he has also reminded us that the war against poverty is no less heroic than military actions. I entirely endorse his views and 1 do hope that the poverty which is still spreading in this country will stop not because of the Government's orders, rules or regulations, but because of the steps that will have to be taken to see that it is not poverty tbat is distributed, that it is not the wealth of the few that is distributed, but conditions are so created to bring about economic prosperity in the country so that everyone of us can share the blessings.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for having given me this opportunity to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Yes, Mr. Lakshmana Gowda.

* SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Mysore): Mr. Vice-Chairman, Sir, with your permission I wish to express my views on the notable Address by President to both Houses of Parliament given in this important year.

There is no doubt that the President has been kind enough to refer to many important matters in his address. Even so, some other matters have not been referred to by him.

* Orginal speech in Kannada.

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

He has begun his address with a reference to Bangla Desh. The courage shown by men and officers of our armed forces in the Bangla Desh Struggle and the firmness with which our Prime Minister acted in getting Bangla Desh liberated deserve our commendation. Our country was able to help Bangla Desh in achieving their independence and for this we have to congratulate the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, for her great rest-raint and commendable fortitude and skill. They discharged their duty despite opposition by many countries of the world and we all congratulate the government and the Prime Minister for this and in so doing I am only doing my duty.

Sir, the President has referred, among other things, to the matter of self-sufficiency in food. We have achieved self-sufficiency although we passed through the problem of war and of refugees. As a result of this recent conflict, the aid that was coming to us from America has been stopped and in such a situation it is imperative that we become self-sufficient and we stand on our own feet and try to solve our problems. This is the main point made by the President and it is heartening to hear these points from the President. We should pay greater attention to agriculture. In recent years the monsoon has been helping us as a result of which our green revolution has been a success and we have had good crops. The President has said that prices should be controlled. The farmer should get all the means so that he is in a position to increase food production and only then can our green revolution succeed. The President has not laid much stress on it.

A lot has been said about land reforms which are very necessary. Every political party is in favour of land reforms. Various laws have also been made to bring about land reforms. But the implementation of these laws has been delayed. We should take immediate steps to confer ownership rights on tenants. This is the first requirement after which many other things can follow. The present laws regarding transfer of ownership rights to tenants cause a lot of delay and the tenants have to take recourse to law courts before they can get the ownership right. Therefore, in my opinion, greater attention should be paid in this direction.

The President has also referred to land ceiling in his Address. Government is trying to bring down the ceiling of land holdings. Efforts in this direction are being made in the States also. But we should not view this matter from a political angle or with an eye on elections. We should not think that lower the ceilings the better it would be. The opinion of experts should be taken in this matter. It is being said that rich people in the villages should be taxed. This step might be well-received in villages. But so far as ceilings are concerned we are not getting the opinion of experts. Some people say that the ceiling should be 6 acres, others feel that it should be 10 acres while many others say that it should be 12 acres. But all this talk is of no avail. Whatever has to be decided should be decided on the advice of experts so that production in agriculture is not affected adversely. If this is not done we might have to face a crisis caused by shortage of food production and stoppage of foodgrain import. It is, therefore, necessary to fix the ceilings in consultation with experts taking into consideration the nature of land and the climatic conditions.

I now come to industries. The President has said in his Address that there is great scope of improvement in the industrial sector and that production in that sector is still not satisfactory. From the recently published Economic Survey Report we learn that the rate of growth, which was 7 per cent in 1969 is not even 3^ % now. This is a matter of great concern. So we should pay greater attention towards industrial development and remove the shortcomings. The way our public sector undertakings are functioning is not a matter of pride for us. While I do feel that the public sector should grow yet it would not be desirable to make good the losses suffered by them due to bad management by increasing taxes. As Mr. Jaipuriajust now said, we should encourage our industries to grow. If we want to become self-reliant, public sector alone cannot help us in becoming self reliant. Mr. Bhupesh Gupta and others have given notice *of* many amendments to the motion of thanks for the Presidents Address. The burden of these amendments is that mixed economy is not good and that we should follow the pattern of Soviet Union and similar other countries. I, however, feel that the mixed economy that we have adopted in our country is good; it has provided sufficient encouragement for development. If

we have both the sectors, it would encourage a healthy competition between the two. The private sector industries are better run than the public sector industries. The production in this sector is also greater while the cost of production is much less. In view of all this I feel that the policy of mixed economy should be continued in the country. The President has not paid any particular attention to this in his Address.

We are now talking of economic Swarajya. I do appreciate the idea. But if we want to achieve economic Swarajya, we shall have to bring about quite a lot of development in the industrial and agricultural sectors. Mr. Jai-puria was saying that the prices of consumer goods have gone up. According to him it is done to the face that excise duty and sales tax have gone up by 20-25 % and it has become difficult for people to purchase things. A perusal of annual budgets reveals the fact that the direct and indirect taxes have been increasing from year to year. How can we make the consumer goods available to the people when the incidence of customs and Sales taxes makes their prices prohibitive? If we do not keep a check on the price line it can lead to serious difficulties. Therefore, this matter should be attended to, Moreover experts are of the view that heavy taxation does not necessarily yield proportionately higher revenue. Some people feel that the incidence of taxation is already very high in this country. We should make a comparative study of the tax structure in other countries to take suitable action on the basis of that.

A reference to the Indo-Soviet Treaty has been made in para 29 of the Address. This treaty is good. This will have to be admitted by all. In the past we had to face many difficulties. Following this treaty we got help from the Soviet Union for which we are thankful. Our Prime Minister deserves praise for the timely conclusion of this treaty.

I would now like to say a few words about commercial crops. In his Address the President spoke about agriculture and industries but he did not speak much about commercial crops. Commercial crops earn foreign exchange for us. If we encourage crops like tea, coffee, rubber, etc. we can benefit the rural people a lot. In the hilly area of Malenad there has been increase in the procurement of commercial crops. It would, therefore, not be good to neglect the commercial crops because through them we can also provide employment to thousands of people.

The President also referred to rural employment and rural housing. Housing facilites in plantations and neighbouring areas have increased. If we can further enlarge this facility it would help greater development of the rural areas. Those who have been able to retain land after the introduction of land reforms, they can construct houses on their own land. But the landless labour have no land to build houses on. They have thus to face the problem of housing therefore Government should pay more attention towards the development of plantations in the hills and rural areas. This could help in eradicating of rural unemployment.

The President has also made a reference to the recent elections. There is a lot of debate going on about elections held in West Bengal between C.P.I. (Marxist) and the CPI. and the Congress. Many things have been said here. I only want to say this, that even though the elections were not properly conducted and even thoughthere were difficulties during the elections, we should not be excited now. The elections have been held and people have elected their representatives. By getting excited we would not be serving the canse of democracy. Elections are now over and people haveelected their representatives. So we should give the elected people a chance to iorm their govern- ments.

After all, elections are held after every five years. After five years when the elections are again held these political parties can again try to win the support of the people and get their candidates elected. Therefore this matter of elections should not be magnified and agitatated. This is what'I wish to tell my C.P.M. friends who along with some other members have been saying that elections were not fair in West Bengal and Jammu and Kashmir. However, the Government and the Election Commission should pay more attention to this problem so that in future people may not be in a position to complain and no blame may come to democracy. We should all bear this in mind.

With these words, Sir, I support the motion of thanks on the President's Address.

Thank you.

SHRT M. N. KAUL (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, let me first deal with one point, namely. the language of the President's Address A point has been made by a number of speakers that the language used is not strong. In particular a number of speakers drew attention to the observation of the President to the effect that there was great disappointment in our country at the lack of sympathy displayed by the Government of the United States of America towards the struggle of the people of Bangladesh for their democratic rights and fundamental freedom. Several speakers stated that this was very mild language, but they omitted to bring to the notice of the House the subsequent sentence which said:

> "Public opinion in the United States of America has expressed this sympathy in abundant measure and has been critical of the policies of the erstwhile military regime of Pakistan. This gives us hope that our relations with the United States of America, based on mutual respect and understanding, will not be allowed to deteriorate."

Now, Sir, as Pandit Jawaharlal Nehru pointed out very early, when this whole procedure of Address by the President was started in our country, the President's Address to Parliament is not intended to be a fighting political speech. It is a pronouncement of importance by the Head of the State. It is true tliat the policies that it enunciates are those of the Government but it is important that in a pronouncement of such great significance made at the opening session of Parliament the language that is used should be one of moderation and dignity. That was the concept which Pandit Jawaharlal Nehru set in all the speeches from the very beginning that so far as President's Address is concerned the words used should be chosen with care and should befit the occasion and the strength in the Address should come from the moderation of the language used.

Apart from that I am not one of those who believe that in international politics once a country is a friend, it is always a friend. I think the basic concept behind non-alignment is that friendships are developed; of course, while they last, they are good and to the benefit of the country but it should always be remembered that it is not our concept that we should make any country a permanent enemy. It is well to remember as the President has pointed out—it is implied in his observations—we should never forget Vietnam. Two American Presidents, perhaps three, have fought to the bitter end tn Vietnam but ultimately the stveghtnh of the Vietnamese people and its reaction on American public opinion compelled the present President to reverse that policy. So we have to balance these two things, the policy of the Government of the day which the Prime Minister has condemned in her political speeches in language that is sutiable for the occasion, and also the public opinion in the a United States, Our ultimate belief must be that public opinion in the United States will gather momentum and force the President to adopt a policy which fits in with the developing circumstances. Already it is reported that the United States will soon recognise Bangla Desh. We should also remember that President Nixon himself was one of the strongest anti-Communists in the United States but he has reversed his policy during his Presidential tenure. So it is well to remember that nations would have certain policies in their own interests and on their own reading of the situation and they are likely to change their policies suddenly and we may not know the timing. Therefore it is well to have a policy of good and friendly relations. Of course we should express our opinion strongly and we have certainly expressed our resentment at the policies of the United States in regard to this matter in a language which is well known to the House.

Now, Sir, in this one year from March 1971 to March 1972 we have compressed history which may have taken decades to develop. That is a vital point so far as this period is concerned. We had a big electoral victory in the elections to the Lok Sabha, then there was the victory in war and now the resounding victory in the elections to the Assemblies. My point is that these three events signify and crystallise the stability and strength of the Government of the country. Today we have a Government which is strong enough to announce its policies and implement them. The crucial test is whether during the remainder of the life of this Parliament Govcn.mcnt will be able to deliver the goods. When I say 'deliver the goods', I mean not that the Goven ment will be able to abolish the age old poverty in the country but what 1 mean is thai there should te policies which will be noticed by the people; that is to say, some changes that are brought about should be clearly visible however small

they may be towards the improvement of the condition of the people. People should feel that there is some progress, that conditions are getting better from year to year and the present feeling that conditions are getting worse, poverty is multiplying and all that should go. That is the vital thing to be remembered in this connection.

Now Sir, I recall to mind an observation which Stalin made to Harriman which he quoted while addressing Members of Parliament here. Stalin said to Harriman in a private conversation that communism breeds in the cesspools of capitalism. Now, it is these cesspools of capitalism which we have to eliminate. Wherever there is oppression, wherever there is extreme poverty, all those places, all those bacilli which are functioning in the various organisations, they have to be eliminated, and they can be eliminated not only by the hard work of the people as a whole, but also by the policies of the Government. At any rate, I have one feeling that in future—I may prove wrong—there may not be many leakages of Government decisions. I am encouraged to make that observation by the recent policy which the Government announced in relation to the Indian Copper Corporation. Now, they took over its control with the ultimate aim of nationalising it, and the people connected with this industry, they did not have an inkling of this decision. Now this is an achievement. To continue to have this sort of achievement Government should after making up their mind, disclose their decisions at once. But there should be thinking behind a decision. It is not that a decision should be taken instantly or haphazardly. Decisions should be well thought out, well considered, and there must be a loyal civil service attached to the Minister, and the business world should not get any inkling of the actual timing of a decision, because that is so vital for the operation of the markets. The markets may, for a while, get jittery, but ultimately they will get used to the announcement of Government policies. Much mischief has been done in the past because there have been leakages of Government decisions, and if these leakages are plugged and Goverumjnt decisions are properly timed, that would have a very healthy influence on the political atmosphere and the business world.

As one British Prime Minister put it, thinkers are vital. And we have a number of thinkers in the present Government, but what is more important is that in a politician there should be a combination of a thinker and a doer. Diagnosis is half cure. We all know the diagnosis. In the many speeches that have been made in the House the diagnosis has been clearly stated. The unemployment problem has to be tackled in all its aspects and particularly the unemployment of the educated youths, because that portion of the unemployed people prove very inflammable and incite other sections all over India, and so, that is one aspect that has to be dealt with quickly in a way so that a sizable impression is made in the solution of that problem. Then the other problem is of the price-line. Now we do not know what we have in store in the Budget, but it has been our experience in the past that because of the great reliance that the Government place on excise revenue, which is raised from year to year, in order to collect more revenues the result is that prices go on rising and remain uncontrolled. Now, unless the prices are controlled, Government's economic policies are likely to founder in many areas, and price level can ultimately be only controlled if productivity increases. I am one of those who believe that a moderate dose of deficit financing is vital for the functioning and development of an under-developed country. You cannot meet all the requirements of theGovern-ment by loans and taxes and a moderate dose of deficit financing is essential. That is recognised, but that has to be regulated over a period and matched by production. If production increases, then the deficit financing is absorbed by the economy.

SHRI MAHAVIR TYAGI: It should nol be a recurring expenditure.

SHRI M. N. KAUL: Certainly it shoulc be for development purposes. When I sait deficit financing I meant for developmen purposes, that is to say, projects should not bi given up for lack of finances. Care should bi taken to see that productivity increases at th, same time. It means that the industries parti cularly in the public sector should be run em ciently by the Government. The Governmen has yet to set a record in the efficient runnin of the industries for which they ar responsible. That is a very vital and importan consideration.

Now, Sir, we have been passing through year which has been one of the most fortunai

[Shri M. N. Kaul]

years in recent memory. We have today emerged as a strong nation, a nation whose Government has behind it the backing of the people. That happens at a time when the international situation is also changing very fast. Imagine in this changing international situation there had been a weak and minority Government, we would have been exploited by all the great powers. Now, the great powers have to be wary of us. We have to watch the situation very carefuily.

There is only one other matter to which I should like to refer in particular and that is Mr. Bhutto's peace offer to India. So far as Mr. Bhutto is concerned, we have to be very cautious in dealing with him. In the first place, we do not know how long he will last and whether a military regime will ultimately emerge in Pakistan. It is no use settling with a leader whose whole position is unstable and who lives on statements made from day to day. I heard his original broadcast when he took over the reins of Government in which he developed a concept of revenge. The other day he developed the concept that Pakistan will develop one of the finest military machines in Asia. Now, he says: "Oh, I am not concerned with Kashmir. I want to settle things gradually." He is making all these statements on the eve of his departure to Moscow. It is clear thut America is not in a position today to play a major role. Therefore, either in his own judgment or on advice, he is now proceeding to Moscow. Why, because he thinks that Moscow has influence with India. He is now approaching Moscow. Now, Moscow will deal with hirn as they think best, but we have to analyse as to what is his objective. To my mind his objective is not to settle any problem with India. He is being pressed and pressed very hard in his own country that he should get the prisoners back and if he does not get the prisoners back he knows that he will be ousted any time. Public opinion may develop against him. Secondly, he wants to get back the lost territories. These are his two objectives, but he should know that he cannot fool India. We cannot just give up these two points without having a settlement which is in the interests of both India and Pakistan. I do not suggest that a settlement should be wholly in favour of India and in the interests of India only, but a well-balanced settlement, which it will be for the Government to determine, a Government which has behind it the backing of Parliament. Any decision that the Government takes will naturally have the majority backing of Parliament.

But that does not mean that they can ignore parliamentary opinion, they have to sense parliamentary opinion. They have to beware of what happened at Tashkent and sbusequent developments. We have to retain those very positions which we gave up at Tashkent. And no one now will give up those advantageous points because—at another occasion we may be put to great difficulties. Of course, the Government of the day is responsible, it must see that the door is kept open for negotiations and all that. If the mind of the Government is made up, there is no danger in the negotiations, in meeting Mr. Bhutto. But its mind must be firmly made up as to what is beneficial to India. The Government in this country knows its mind and knows when to act and how to act.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. THE APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1972

II. THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL, 1972

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

0)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation (Railways) Bill, 1972 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16lh March, 1972.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(2) "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1972, as passed by Lok